twitter.com/divyadelhi | facebook.com/divyadelhi | infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

DD

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | गुरूवार, 07 अगस्त, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 262, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

पंजाब: लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में भाजपा निकालेगी 'जमीन बचाओ किसान बचाओ' यात्रा

चंडीगढ़

पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्य सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। भाजपा 17 अगस्त से 5 सितंबर तक जमीन बचाओ, किसान बचाओ नाम से यात्रा निकालेगी। यह यात्रा पटियाला से शुरू होकर पठानकोट में संपन्न होगी। यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरेगी, जहां पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए हैं। भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों ने बुधवार को कहा कि पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है और इस यात्रा का उद्देश्य किसानों की जमीन और अधिकारों की रक्षा करना है। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हम शामिल हुए। हमने वादा किया कि हम चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़े हैं।उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की रोजी-रोटी खेतों से जुड़ी है। अगर किसानों की जमीन ही नहीं रहेगी, तो हम कंगाल हो जाएंगे। सरकार ने लैंड पूलिंग के तहत 6563 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का फैसला लिया है। यह जमीन हड़पने की कोशिश है, जिसे बिल्डरों को दिया जाना है। इसका मकसद आने वाले चुनावों के लिए फंड जुटाना है।

भाजपा जल्द शुरू करेगी पंजाब में किसान सुरक्षा आंदोलन: चुग

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बुधवार को आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हाल ही में शुरू की गई लैंड पूलिंग योजना के माध्यम से दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारियों से 30,000 करोड़ रुपये का गुप्त सौदा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से इस कथित सौदे पर स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में किसान सुरक्षा आंदोलन चलाएगी। बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर तरुण चुग ने लैंड पूलिंग योजना को पंजाब की जमीन की लूट करार दिया।

ट्रंप ने भारत पर लगाया 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ

भारत ने अमेरिका के 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को बताया 'अनुचित',

नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह पहले लगाए गए 25 फीसदी टैरफि से अतिरिक्त होगा। इस तरह भारत पर अब 50 फीसदी टैरफि होगा। भारत के साथ व्यापार तनाव को और तेज करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यह बढ़कर कुल 50 फीसदी हो गया है। इससे पहले 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है। उन्होंने घोषणा की थी कि वह अगले 24 घंटों में नई दिल्ली पर टैरिफ "काफी हद तक" बढ़ा देंगे क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप की ओर से साइन किए गए आदेश के मुताबिक यह टैरिफ 21 दिनों के भीतर प्रभाव में आएगा, जो 27 अगस्त, 2025 से भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले सामानों पर लागू होगा। हालांकि, जो वस्तुएं इस तारीख से पहले रवाना हो चुकी होंगी, वो 17 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका पहुंच जाएंगी, उन्हें इस शुल्क से छूट मिलेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह टैरिफ अन्य सभी

शुल्कों और टैक्स के अतिरिक होगा, जबकि कुछ खास मामलों में छूट भी दी जा सकती है।

ट्रम्प की धमकी से डरे 100 से ज्यादा देश: अमेरिका से ट्रेड डील की, भारत समेत 5 देश नहीं झुके

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी लगातार घाटे में जा रही है। इस नुकसान से बचने के लिए हम उन सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे, जो हमारे सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने करीब एक महीने बाद 2 अप्रैल को भारत समेत 69 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह 9 अप्रैल से लागू होने वाला था,

भारत कैसे हो जाएगा प्रतिस्पर्धा से बाहर

इस साल अप्रैल से पहले भारतीय फुटवियर पर आठ प्रतिशत का शुल्क लगता था तो अब अमेरिका होने वाले फुटवियर के निर्यात पर 50 और आठ यानी कि 58 प्रतिशत का शुल्क लगेगा। निर्यातकों का कहना है कि अब अमेरिका के बाजार में प्रतिद्वंद्वी देश का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका में निर्यात करने वाले देशों में ब्राजील को छोड़ किसी भी अन्य देश पर 50 प्रतिशत का शुल्क नहीं लगाया गया है। यहां तक कि गत मई-जून तक चीन को लगातार भला-बुरा कहने वाले ट्रंप ने चीन पर 30 प्रतिशत का ही शुल्क लगा रखा है और अब चीन के साथ व्यापारिक समझौते की बात भी अमेरिका कर रहा है। चीन के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक शुल्क की वजह से अमेरिका के खरीदार अब फिर से चीन को ऑर्डर देने लगेंगे। पिछले तीन महीनों से भारत पर मात्र 10 प्रतिशत का शुल्क लग रहा था जिससे अमेरिकी खरीदार अपैरल, फुटवियर, खिलौने, जेम्स व ज्वैलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में चीन की जगह भारत से खरीदारी करना पसंद कर रहे थे। इस साल अप्रैल-जून में अमेरिका होने वाले भारतीय निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

राष्ट्रीय हित में उठाएंगे सभी आवश्यक कदम: भारत

नई दिल्ली

भारत ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को अनुचित करार देते हुए कहा कि देश अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा। भारत का कहना है कि अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों में रूस से आयात कर रहे हैं। ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाना अनुचित और समझ से परे है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जारी टैरिफ संबंधी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उक्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा। प्रवक्ता ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हमारा आयात बाजार

कारकों पर आधारित है तथा इसका समग्र उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत को निशाना बना रहे ट्रंप

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्रंप के फैसले को आर्थिक ब्लैकमेल बताते हुए सरकार से दबाव में नहीं आने को लेकर सचेत करते हुए कि ट्रंप अनुचित समझौते के लिए धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका के पारस्परिक शुल्क की घोषणा से पहले जो शुल्क भारतीय वस्तुओं पर लागू हो रहा था, उसे भी जोड़ा जाएगा। हालांकि दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर स्मार्टफोन को पहले की तरह इस शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है।

इन वस्तुओं पर इस साल अप्रैल से पहले वाले शुल्क मान्य होंगे। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2024 में चीन ने रूस से 62 अरब डॉलर के तेल की खरीदारी की जबकि भारत की यह खरीदारी 52 अरब डालर की थी। फिर भी ट्रंप अब चीन की जगह भारत को निशाना बना रहे हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की।

अमृतकाल में कर्तव्य भवन से तय होगी देश की दिशा: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में नव-निर्मित 'कर्तव्य भवन' का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह भवन केवल एक सरकारी इमारत नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का प्रतीक और यह राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करने वाला केंद्र बनेगा। कर्तव्य पथ पर आयोजित एक भव्य सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कर्तव्य शब्द केवल कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों तक ही सीमित नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है, जो कर्म प्रधान दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने भगवद्गीता का उल्लेख करते हुए

कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने भी कर्तव्य को सर्वोपरि माना है। उन्होंने कहा, कर्तव्य केवल अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व की भावना से जुड़ा है, जो देश के भविष्य की आधारशिला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बहुत विचार-विमर्श के बाद इस भवन का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है। यह नाम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक जीवंत विचार है जो नीतियों, योजनाओं और फैसलों के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि अमृतकाल में यह भवन नीतिगत निर्णयों का मुख्य केंद्र बनेगा, जहां से आने वाले दशकों की दिशा तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण से जुड़े जो भी निर्णय होंगे, वे अब इन नए भवनों से संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जैसे स्मारक आधुनिक भारत के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार विकास के इस दौर में केवल इमारतें नहीं बना रही, बल्कि नई सोच, नई दिशा और नए भारत की नींव रख रही है।

धराली: सरकार ने राहत व बचाव कार्य में झोंकी ताकत

नई दिल्ली

उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद निचले हर्षिल क्षेत्र में एक शिविर से लापता भारतीय सेना के जवानों के बारे में कोई खबर नहीं है। इसके बावजूद भारतीय सेना के जवानों ने राहत कार्य तेज कर दिया है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। गंगोत्री और धराली में दो अतिरिक्त बचाव और राहत टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हर्षिल से धराली तक सड़क मार्ग खोलने के लिए मिट्टी हटाने वाले उपकरण तैनात किए गए हैं। फंसे हुए नागरिकों का पता लगाने के लिए ड्रोन और बचाव कुत्तों की मदद ली जा रही है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि निचले हर्षिल क्षेत्र में एक शिविर से 8-10 भारतीय सेना के जवान लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में अपने ही लोगों के लापता होने के बावजूद भारतीय सेना के जवान राहत कार्यों में लगे हुए हैं। सेना ने बुधवार को एक बयान में बताया कि उत्तराखंड के धराली में भूस्खलन के बाद अब तक 70 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। गंगोत्री और धराली में दो अतिरिक्त बचाव और राहत टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हर्षिल से धराली तक सड़क मार्ग खोलने के लिए मिट्टी हटाने वाले उपकरण तैनात किए गए हैं। फंसे हुए नागरिकों का पता लगाने के लिए ड्रोन और बचाव कुत्तों की मदद ली जा रही है। निकाले गए लोगों को चिकित्सा सहायता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद बचाव दल का नेतृत्व कर रहे 14वीं राजपूताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन ने बताया कि धराली के खीरगाढ़ में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद 150 कर्मियों के साथ महत्वपूर्ण बचाव और राहत कार्यों में लगे हुए हैं।

राजनीतिक दल एसआईआर पर भ्रम न फैलायें, सुधार के लिए दर्ज करायें आपत्ति: चुनाव आयोग

नई दिल्ली

चुनाव आयोग लगातार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत राजनीतिक दलों से भ्रम न फैलाने और प्रक्रिया में भागीदारी की अपील कर रहा है। आयोग का कहना है कि नियम के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। हर स्तर पर राजनीतिक दलों से जानकारी साझा की जा रही

है। अभी तक दलों की ओर से कोई आपत्ति या दावे नहीं आए हैं। आयोग ने आज एक बयान जारी कर बताया कि जमीनी स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया में राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया में जिनके नाम हटाये गए हैं उनकी जानकारी भी राजनीतिक दलों से साझा की गई है। उनसे अपील की गई है कि वे अपनी आपत्तियां और दावे एक माह के भीतर दे सकते हैं।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विश्वामित्री नदी पर पुल का निर्माण पूरा

नई दिल्ली

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत गुजरात के वडोदरा जिले में विश्वामित्री नदी पर पुल का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। यह पुल परियोजना के लिए गुजरात में निर्मित किए जाने वाले कुल 21 नदी पुलों में से 17वां है। यह पुल 80 मीटर लंबा है और पश्चिम रेलवे की वडोदरा-सूरत मुख्य लाइन के निकट स्थित है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने बुधवार को एक बयान में बताया कि इसके निर्माण में एसबीएस (स्पैन बाय स्पैन) विधि का उपयोग किया गया है। पुल के पियर्स की ऊंचाई 26 से 29.5 मीटर तक है।

आज अपनी विरासत, विकास और शिक्षा पर गौरव कर रहा उत्तर प्रदेश: योगी

मुरादाबाद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुरादाबाद में 79 करोड़ की लागत से निर्मित अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर के सत्ता में आते थे, वे आज घर के हैं न घाट के। ऐसे लोग ना तो समाज के साथ खड़े हो पाए, न ही भविष्य की पीढ़ी के साथ। सीएम योगी ने साफ कहा कि भाजपा की योजनाएं तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर आधारित हैं जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचती हैं। उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि एक दौर था जब तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए सत्ता केवल एक दुकान थी। उन्होंने शिक्षा को नकल, अराजकता और जातिवाद का अड्डा बना दिया था। लेकिन आज वही

लोग संतुष्टीकरण को लेकर परेशान हैं। हमारी सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के मार्ग पर चलती है। इसीलिए जनता का विश्वास आज भाजपा के साथ है। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के लोगों को रक्षा बंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और घोषणा की कि 8, 9, 10 अगस्त को प्रदेश की सभी बहनों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी।

श्रमिकों के धन की बंद हुई बंदरबांट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा बंधन के पर्व से ठीक पहले इस शिक्षा केंद्र को मुरादाबाद मंडल के बच्चों और श्रमिक परिवारों को समर्पित करते हुए इसे अटल जी की स्मृति को समर्पित आदर्श शिक्षा मंदिर बताया। 79 करोड़ की लागत से बने इस विद्यालय को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशताब्दी वर्ष में शुरू किया गया है, जिससे नई पीढ़ी में उनके आदर्श और मूल्य स्थापित हो सकें। सीएम योगी ने बताया कि यह विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि संस्कार, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का भी स्त्रोत बनेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीओसी फंड के सार्थक उपयोग की दिशा में दिए गए निदेर्शों का हवाला देते हुए कहा कि अब यह धन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो रहा है। पहले की सरकारों में यही धन बंदरबांट और भ्रष्टाचार का जरिया बन चुका था। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित हो चुके हैं, जो 18,000 से अधिक श्रमिक और अनाथ बच्चों को पूरी तरह निशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने इसे शिक्षा के प्रति सरकार की अटल प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में भाजपा सरकार ने नकल को समाप्त कर ईमानदार व्यवस्था लागू की है, जिससे उत्तर प्रदेश अब शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे और पांचवें स्थान तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण तकनीक, सीनियर-जूनियर हॉस्टल, संपूर्ण आवासीय सुविधा, स्पोर्ट्स, लैब, और कौशल विकास की व्यापक व्यवस्थाएं हैं।

'परीक्षा पे चर्चा' को मिला गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3.53 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 21 करोड़ से अधिक टीवी दर्शक

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रमुख पहल 'परीक्षा पे चर्चा' (पीपीसी) को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। शिक्षा मंत्रालय और माईगॉव के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को 'एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण' के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह पीपीसी का आठवां संस्करण था। इस कार्यक्रम ने 3.53 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 21 करोड़ से अधिक टीवी दर्शकों के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है।

यहां आयोजित समारोह में आधिकारिक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणपत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक ऋषिनाथ ने इस रिकॉर्ड को मान्य और घोषित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने इस गौरवपूर्ण अवसर पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणपत्र स्वीकार किया। इस मौके पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, माईगॉव के सीईओ नंद कुमारम और शिक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अन्य प्रमुख हितधारक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, स्कूलों और देशभर के शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित होने वाला 'परीक्षा पे चर्चा' आज न केवल छात्रों के लिए बहुप्रतीक्षित संवाद बन चुका है, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी उत्सव का रूप ले चुका है। यह कार्यक्रम परीक्षा के तनाव को कम करने, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने और समग्र रूप से एक आनंदमयी शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने परीक्षा पे चर्चा को प्रधानमंत्री मोदी की एक अनूठी पहल बताया, जो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक साथ लाकर उनके स्वास्थ्य और तनाव-मुक्त शिक्षा को बढ़ावा देती है। उन्होंने इस अमृतकाल में छात्रों के लिए उपलब्ध करियर के व्यापक अवसरों पर प्रकाश डाला और कहा कि सबसे ज़्यादा पंजीकरण का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पहल में जनता के मज़बूत विश्वास को दर्शाता है।

राहुल गांधी भारतीय नहीं, पाक-बांग्लादेशी सोच के हैं : डॉ. हिमंत बिस्व सरमा

एजेंसी

तामुलपुर (असम)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला करते हुए उन्हें भारत विरोधी बताया और आरोप लगाया कि उनकी सोच भारतीय मूल्यों की बजाय पाकिस्तान और बांग्लादेश की मानसिकता से मेल खाती है। मुख्यमंत्री ने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर) के तामुलपुर में भाजपा की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के साथ नहीं हैं। वह भारत के साथ नहीं हैं। यह

बयान उस वक्त आया जब भाजपा 'बीजेपी फार प्रोग्रेसिव बीटीआर' नामक अभियान के तहत बीटीआर क्षेत्र के चारों जिलों - कोकराझाड़, बाक्सा, चिरांग और उदालगुड़ी में सघन जनसंपर्क कर रही है। इस चुनावी अभियान की अगुवाई स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए अन्य भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर सीएए और बेदखली अभियान का विरोध कर अतिक्रमणकारियों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। पार्टी की सख्त बेदखली नीति को विशेष रूप से अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उदालगुड़ी जिले में मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उन्हें नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच जैसे संगठनों और हास्य कलाकार बुलबुल शर्मा का समर्थन भी मिला, जिन्होंने भाजपा की स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर उठाई जा रही मांगों का समर्थन किया। भाजपा ने आगामी 7, 12 और 13 अगस्त को बीटीआर की 12 परिषद सीटों में बैठकें तय की हैं। इसके अलावा, धुबड़ी और ग्वालपाड़ा में भी चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। भाजपा इन चुनावों को कानून-व्यवस्था और मूलनिवासियों के अधिकारों को लेकर जनमत संग्रह के तौर पर देख रही है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी नीति को चुनावी मुद्दा बना रही है।

कर्नाटक में अनुसूचितों को अंदरूनी आरक्षण पर नागमोहन दास आयोग ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट

बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जातियों के अंदरूनी आरक्षण को लेकर बने न्यायमूर्ति एचएन नागमोहनदास आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सौंप दी है। आयोग की 1766 पृष्ठों वाली विस्तृत रिपोर्ट में छह महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल की गई हैं। इसके साथ ही राज्य में लगभग 30 वर्ष से चल रहे अंदरूनी आरक्षण के संघर्ष अब सफल होने की कगार पर है। दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकारों को है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। कोर्ट ने इसे सामाजिक न्याय का विस्तार करार देते हुए कहा था कि यह किसी समुदाय

के आरक्षण अधिकारों को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति एचएन नागमोहनदास के नेतृत्व में आयोग गठन किया था। आयोग ने 27 मार्च 2025 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए व्यापक और सटीक डेटा संग्रह की आवश्यकता बताई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल एक समग्र सर्वेक्षण का निर्णय लिया। विशिष्ट जातियों के आरक्षण की कार्यान्वयन संबंधी अध्ययन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एचएन नागमोहन दास की समिति ने आज अपनी अध्ययन रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सर्वेक्षण के डेटा और विवरणों के साथ मिलाकर कुल लगभग 1766 पृष्ठों और 6 सिफारिशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को सामाजिक न्याय के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

सांसद सुधा की चेन छीनने की घटना को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में कांग्रेस सांसद आर. सुधा से चेन छीनने की घटना को लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसदों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली के दूतावास क्षेत्र को आमतौर पर सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है, ऐसे में वहां एक महिला सांसद के साथ इस तरह की घटना का होना बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि जब आर. सुधा ने पास में मौजूद पुलिस वाहन से मदद मांगी तो उन्हें उचित जवाब नहीं मिला। प्रियंका ने कहा, अगर एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो आम महिलाओं की हालत की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह साफ है कि पुलिस और प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील और सतर्क होने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस घटना को भाजपा सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। दिल्ली में महिला सांसद की चेन छीन ली जाती है, बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। इससे साफ है कि भाजपा शासन में जनता सुरक्षित नहीं है। केरल के सांसद कांग्रेस हिबी ईडन ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सुधा जी ने पास के पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राष्ट्रपति से मिले विभिन्न राज्यों के प्रमुख जनजातीय प्रतिनिधि

एजेंसी

नई दिल्ली। विभिन्न राज्यों से आए प्रमुख जनजातीय प्रतिनिधियों के एक समूह ने 'आदि कर्मयोगी अभियान' के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में भेंट की। वे जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'आदि कर्मयोगी अभियान' के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन आए थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय के शिक्षित लोगों को अपने समुदाय के लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए और उन्हें इनका लाभ दिलाने में मदद करनी चाहिए। उन्हें विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों को भी साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल, जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम

और जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री दुर्गादास उइके भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने जनजातीय प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और उन्हें समुदाय के लिए प्रेरणास्रोत बनने का आह्वान किया।

उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के 'आदि कर्मयोगी अभियान' की शुरुआत 27 जून 2025 को की गई थी। यह अभियान विशेष रूप से शिक्षित, सक्रिय और समाजसेवा में रुचि रखने वाले जनजातीय युवाओं तथा समुदाय के प्रमुख लोगों को जोड़ता है। अभियान के अंतर्गत चयनित आदि कर्मयोगी को सरकारी योजनाओं, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आजीविका और अधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर समुदाय को जागरूक करते हैं, लोगों को योजनाओं की जानकारी देते हैं और उनका लाभ उठाने में मार्गदर्शन करते हैं।

सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान देते है राहुल गांधी: भाजपा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणियों को लेकर उनपर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान देते हैं।भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है

कि राहुल गांधी की एक याचिका आज उच्चतम न्यायालय में लगी थी, जहां पर उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की भारतीयता पर इतनी गंभीर टिप्पणी की है। हर भारतीय इस बात से आहत है कि एक भारतीय विश्व में सबसे वीर भारतीय सेना के विषय में ये कैसे कह सकता है कि वो चीन से पिट रही है। राहुल गांधी चीन के साथ हैं।भाजपा प्रवक्ता भाटिया ने कहा कि जब गलवान में हमारी सेना ने शौर्य दिखाकर चीनी सेना को खदेड़ दिया था, तो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चीन ने 2 हजार वर्ग किमी की भूमि को कब्जा लिया है, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। जिस संविधान को राहुल गांधी हाथ में लेकर घूमते हैं, उसको तार-तार करने का जिम्मा भी राहुल गांधी ने ही उठा रखा है। हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राहुल ने वर्ष 2020 में चीन के साथ हुए गलवान घाटी संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में यह टिप्पणी की थी। विगत 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस बयान को आधार बना कर बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था।

बाढ़ में फंसे सवा लाख लोगों तक योगी सरकार ने पहुंचाई राहत, राज्य के 17 जिले प्रभावित

एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश के बाद अतिसंवेदनशील और संवेदनशील जिलों के अधिकारी हरकत में आ गये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी अपने जिलों में बाढ़ की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें भी मुस्तैदी से लोगों को राहत देने में लगी हुई हैं। बाढ़ के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के 57 जिलों में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 15 और पीएसी की 48 टीमों को तैनात किया गया है। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों की 40 तहसीलें और 694 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में बाढ़ से 1,16,403 लोग प्रभावित हैं। इन सभी को राहत पहुंचाई गयी है। वहीं बाढ़ की वजह से 4,682 मवेशियों को सुरक्षा स्थान पर शिफ्ट किया गया है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 373 लोगों के मकानों को क्षति पहुंची है, जिनमें से 356 लोगों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 11,386 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में आया है। इन प्रभावित क्षेत्रों में 738 नावों और मोटरबोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा

रही है। इसके अलावा 4,867 नावों को प्रीपोजीशंड किया गया है। इन इलाकों में अब तक 9,467 खाद्यान्न पैकेट और 1,18,769 लंच पैकेट वितरित किये जा चुके हैं। वर्तमान में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 39 लंगर के जरिये पीड़ितों को भोजन की सुविधा दी जा रही है। योगी सरकार के निर्देश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के साथ मवेशियों की सुरक्षा और उनके खाने-पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तक मवेशियों के लिए 2,234 कुंटल भूसा वितरित जा चुका है। इसके अलावा 1,57,168 क्लोरीन टेबलेट और 1,21,476 ओआरएस पैकेट भी वितरित किए जा चुके हैं ताकि जलजनित बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 924 बाढ़ शरणालय सक्रिय हैं, जहां 18,772 लोग अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। वहीं अब तक इन सभी का 778 मेडिकल टीमों द्वारा मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। इसके साथ ही 1,193 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है, जो प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निगरानी रख रही हैं। अब तक 25,586 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाज़ीपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों की ओर से पेट्रोलिंग की जा रही है।

ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की उपाध्यक्ष ने की राज्यसभा के उपसभापति से मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की उपाध्यक्ष नुसरत गनी ने संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पीठासीन अधिकारियों ने नियमित संसदीय आदान-प्रदान सहित भारत और ब्रिटेन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। हरिवंश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ब्रिटेन की सफल यात्रा, जिसके दौरान ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर के मद्देनजर दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि का विश्वास भी व्यक्त किया। उपाध्यक्ष गनी संसद संचालन समूह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की अध्यक्ष हैं और भारतीय संसद के कामकाज में एआई के अनुप्रयोग का पता लगाने के लिए भारत का दौरा कर रही हैं। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत और ब्रिटेन अपने साझा इतिहास, मूल्यों और लोकतांत्रिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संसदों के लिए उत्तरदायी प्रौद्योगिकी ढांचे को आकार देने में वैश्विक प्रयासों का संयुक्त रूप से नेतृत्व करने की विशिष्ट स्थिति में हैं। एआई के महत्व पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी उपकरण है जो संसद के कामकाज में सहयोग प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों के लिए एआई उपकरणों का प्रभावी ढंग से

उपयोग करने को लेकर नियमित विशेषज्ञ सत्र और कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। नुसरत गनी ने संसद में एआई के उपयोग और संस्थान द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में प्राप्त प्रगति पर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिक प्रस्तुतियों की सराहना की। उपाध्यक्ष गनी की यह यात्रा लोकसभा अध्यक्ष की जनवरी 2025 में ब्रिटेन यात्रा के बाद हो रही है, जहां हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के साथ बातचीत के दौरान भारतीय संसद में एआई के उपयोग पर प्रकाश डाला गया था।

जाति और धर्म आधारित आदेश पर सीएम योगी नाराज, अधिकारी सस्पेंड

एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के उस आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को खास जाति (यादव) और धर्म (मुस्लिम) से जोड़कर निर्देशित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की भाषा और सोच न सिर्फ शासन की नीति के खिलाफ है, बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने वाली है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष, तथ्यों और कानून के अनुसार होनी चाहिए, न

कि जाति या धर्म के आधार पर।उन्होंने यह भी कहा कि आगे से ऐसी गलती न हो, इसका सख्त ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार समरसता, सामाजिक न्याय और सभी के समान अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियां किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं हो सकतीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की नीति संविधान और न्याय की मूल भावना पर आधारित है, न कि किसी भेदभाव पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों को भी घेरा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म के बढ़ते गौरव से कांग्रेस और सपा परेशान हैं। पहले की सरकारें आतंकियों को संरक्षण देती थीं और सनातन धर्म की परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास करती थीं, लेकिन अब भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सहारनपुर क्षेत्र की उपेक्षा को समाप्त कर दिया है और विकास तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक नया अध्याय शुरू किया है।

मायावती ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर जताया शोक

एजेंसी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक व आदिवासी समाज के जाने-माने दिग्गज नेता शिबू सोरेन का आज निधन हो जाने की खबर अति-दुखद है। उनके पुत्र तथा वर्तमान में झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन व उनके परिवार के साथ-साथ उनके समस्त समर्थकों एवं अनुयाइयों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। उल्लेखनीय है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। शिबू सोरेन किडनी से जुड़ी बीमारी के चलते पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। हेमंत सोरेन ने अपने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है।

एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की 'वोट अधिकार यात्रा' स्थगित

एजेंसी

पटना। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस ने 10 अगस्त को 'वोट अधिकार यात्रा' निकालने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इसकी जानकारी राजद ने दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने वोट अधिकार यात्रा को स्थगित करने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 'वोट अधिकार यात्रा' को आगे बढ़ाया गया है। पहले यह यात्रा

राखी के बाद 10 अगस्त से होनी थी। हालांकि, यात्रा की नई तारीख अभी जारी नहीं की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के 'वोट अधिकार यात्रा' कार्यक्रम की सूचना निर्गत की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से यात्रा कार्यक्रम की तिथि में बदलाव हुआ है, इसलिए नई तिथि की घोषणा तक इस सूचना को निरस्त माना जाए। आगामी कार्यक्रम की सूचना समय पर दी जाएगी। बता दें कि बिहार मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त को पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। राज्य के सभी 38 जिलों के लिए जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम पटना जिले में कटे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मधुबनी और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है।

किन्नर का गला रेतकर हत्या

एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्या की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना की सूचना दोपहर 1:32 बजे पुलिस को मिली, जब एक महिला पर चाकू से हमला किए जाने की पीसीआर कॉल पांडव नगर थाने में दर्ज हुई। जांच में यह स्थान मधु विहार थाना क्षेत्र में पाया गया। जिसके बाद इंस्पेक्टर मधु विहार मौके पर पहुंचे। पुलिस को हसनपुर की ओर जाने वाले पुल के नीचे एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। जिसकी गर्दन तेजधार हथियार से रेता गया था। मृतक की पहचान करण उर्फ अन्नू (25) के रूप में हुई है। मृतक की लैंगिक पहचान किन्नर थी और वह पिछले 6-7 वर्षों से इस समुदाय से जुड़कर कार्य कर रहा था। वर्तमान में वह गांव चिल्ला में रह रहा था। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि हत्या में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था। जिसकी पहचान कर ली गई है। फिलहाल उसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस दोनों आरोपितों की भूमिका और हत्या के पीछे की वजह की गहराई से जांच कर रही है।

होलम्बी कलां में बरामद देसी बमों का सफल निस्तारण

नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले के होलम्बी कलां क्षेत्र में वर्ष 2023 में बरामद किए गए 10 देसी बमों का सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में सुरक्षित रूप से निस्तारण कर दिया गया। यह बम एफआईआर नंबर 358/25 (धारा 286 आईपीसी एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3/4/5) के तहत थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज मामले के दौरान जब्त किए गए थे। पुलिस के अनुसार, इन देसी बमों को शुरू में एक सुरक्षित एवं अलग भूखंड में गहराई में दफन कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया था। इसके बाद इनके सुरक्षित निस्तारण के लिए संबंधित एजेंसियों को औपचारिक अनुरोध भेजा गया। अनुरोध पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), बाहरी उत्तरी जिले की बम डिस्पोजल टीम और एफएसएल रोहिणी की टीम मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और सभी देसी बमों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर नष्ट किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे की जांच एवं कानूनी प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण थी।

सड़क हादसे में युवक की मौत

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिले के वसंत कुंज नॉर्थ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। घटना सुबह करीब 6:30 बजे नेल्सन मंडेला मार्ग पर वसंत विहार से वसंत कुंज की ओर जाते समय हुई। पुलिस को सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के सामने एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर दुर्घटनाग्रस्त हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर कोई घायल व्यक्ति नहीं मिला। कुछ ही देर बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर से सूचना मिली कि मुनिरका निवासी राजकुमार (40) को सड़क दुर्घटना में घायल हालत में लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। वहीं पुलिस जांच में यह सामने आया कि दुर्घटना में टक्कर मारने वाला वाहन एक टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कार थी, जिसकी पहचान कर ली गई है। फिलहाल पुलिस स्थानीय स्तर पर जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राहुल गांधी को केसी त्यागी ने दी नसीहत, बयान देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारतीय सेना के बारे में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए कड़ी फटकार लगाई गई। कोर्ट की फटकार लगाए जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) नेता केसी त्यागी ने उन्हें नसीहत दी है कि वह बयान देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। आईएएनएस से बातचीत के दौरान, केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोई भी बयान देने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए ताकि उनकी किरकिरी या जग हंसाई न हो। इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने कहा कि अदालत की टिप्पणियों से विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के आचरण पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

हेगड़े ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। उनकी स्थिति स्वयं ही जांच के दायरे में आ गई है। न्यायाधीशों ने सवाल किया कि उनके पास यह दावा करने का क्या सबूत है कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन संसद के बजाय सोशल मीडिया पर निराधार दावे करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए नुकसानदेह है। हेगड़े ने कहा कि राहुल गांधी संसदीय बहसों में भाग लेने के बजाय बयानबाजी को प्राथमिकता देते हैं। अदालत ने भी इस पर टिप्पणी की है। यह विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका को कमजोर करता है।

यह मामला राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई बयानबाजी से जुड़ा है। कांग्रेस सांसद ने कथित तौर पर कहा था, चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं और 9 दिसंबर, 2022 को तवांग सेक्टर में हुई झड़प का जिक्र किया था न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विपक्ष के नेता गांधी के इस दावे पर असहमति जताई कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर वह एक सच्चे भारतीय होते, तो यह सब नहीं कहते।

विधानसभा में दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 पेश

एजेंसी

नई दिल्ली।दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पेश किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी के उन पुराने और जटिल मुद्दों को सुलझाने में जुटी है, जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया। निजी स्कूलों की लगातार फीस बढ़ोतरी से छात्रों के अभिभावक वर्षों से परेशान हो रहे हैं और अब इस लंबे अन्याय पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ठोस और निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा रही है कि शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार न बने, बल्कि हर बच्चे का अधिकार हो। आज उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा की सरकार शिक्षा

को सुलभ, समान और गुणवत्ता-युक्त बना रही है। शिक्षा मंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज करते हुए कहा कि छात्रों के अभिभावक वर्षों तक स्कूलों से लड़ते रहे, कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते रहे, लेकिन पिछली सरकारें चुप रहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सदन पटल पर वर्ष 2023-24 के दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार से संबंधित 'वर्ष 2023-24 के राज्य वित्त' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल अनुदान और विनियोग 81,918.23 रुपये करोड़ के प्रति 15,327.36 करोड़ रुपये (18.71 प्रतिशत) की कुल बचत हुई।

कुल बचत का 8,376.40 करोड़ रुपये (54.65 प्रतिशत) अभ्यर्पित करने में देरी के कारण 31 मार्च 2024 को व्यपगत हो गया। इससे पहले ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सदन पटल पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2024 के संबंध में अधिसूचना, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का वर्ष 2023-24 लिए वार्षिक लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में 1971 की घटना का दिया हवाला

एजेंसी

नई दिल्ली। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि की घोषणा का खंडन किया। उन्होंने इस कदम को रूस के साथ भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंधों को लेकर दबाव बनाने का एक गुमराह प्रयास बताया। मनीष तिवारी ने कहा कि टैरिफ वृद्धि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कम नहीं करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके देश ने 1971 में दक्षिण एशिया के राजनीतिक मानचित्र को बदलने से रोकने के लिए बंगाल की खाड़ी में सातवां बेड़ा भेजा था। हमने उसका सामना किया। एक राष्ट्र के रूप में हममें आपके टैरिफ के खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी कि वे भारत पर टैरिफ में काफी वृद्धि करेंगे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि भारत बड़े मुनाफे के लिए खुले बाजार में रूसी तेल बेच रहा है।

उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बड़े मुनाफे के लिए बेच रहा है। उन्होंने कहा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं।

इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी वृद्धि करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के अलावा अतिरिक्त टैरिफ कितना होगा।

राहुल गांधी भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं - अनुराग ढांडा

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में चीन और भारतीय सेना को लेकर दिए बयान पर सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। इसको लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक?ता अनुराग ढांडा ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं। अनुराग ढांडा ने बातचीत में कहा कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं। जब भारत-पाकिस?तान के बीच तनाव होता है, तो कहते हैं कि हमारे कितने जहाज गिराए गए, इसकी जानकारी दो। भाजपा जिन सवालों में घिर रही होती है, वहां लूज बॉल डालना कांग्रेस और राहुल गांधी का काम रहा है। यह भाजपा के साथ मिलकर खेलते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर विपक्ष की जिम?मेदारी है कि तथ?यों के आधार पर सरकार से सवाल पूछे, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि तथ्यों के आधार पर सही जानकारी देती रहे। सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि चीन के साथ विवाद में कब क्या हुआ। उन्होंने पूछा

कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन इसके बाद भी कौन से ऐसे तथ्य और कारण थे जिनकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पीएम मोदी को झुकना पड़ा जब सरकार सही तथ्य नहीं बताएगी तो गलत साक्ष्य सामने आएंगे। इसमें सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष कांग्रेस पार्टी दोनों पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। इसी वजह से देश में तरह-तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। हर मुद्दे पर हम अपना पक्ष रखते हैं। मुद्दों के आधार पर समय-समय पर जिस भी पार्टी से बातचीत की जरूरत महसूस होगी, हम करेंगे। लेकिन किसी भी अलायंस का हिस्सा आप नहीं हैं। गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी का कोई प्रश्न नहीं उठता। पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आज जो यह क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है, यह इस बात पर मुहर लगाती है। पार्टी को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। नेताओं के खिलाफ फर्जी केस तक दर्ज किए गए, कई साल तक जांच चलती रही।

निजी स्कूल फीस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध तेज, आतिशी और संजीव झा ने साधा सरकार पर निशाना

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है, जो पूरी तरह निजी स्कूल मालिकों के हितों की रक्षा करता है, न कि छात्रों और अभिभावकों की। आतिशी ने कहा कि यह बिल पहले अप्रैल में पास किए जाने की बात कही गई थी, फिर मई में इसे अध्यादेश के जरिए लाने की बात हुई, और अब कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि बीते चार महीनों में इस बिल को जानबूझकर विधानसभा में पेश नहीं किया गया ताकि स्कूल प्रबंधनों को मनमानी फीस वसूलने की छूट मिलती रहे। उन्होंने कहा, इस बिल में कहीं नहीं लिखा गया है कि 2024-25 में जो फीस बढ़ाई गई है, उस पर कोई रोक लगेगी। न ही 13 पन्नों के इस बिल में फीस का ऑडिट कराने का कोई प्रावधान है। यहां तक कि फीस बढ़ाने की समिति की अध्यक्षता भी स्कूल का प्रबंधन ही करेगा। यानी स्कूल जैसा कहेगा, वैसा ही माना जाएगा। यह बिल साफ तौर पर स्कूल मालिकों को बचाने के लिए लाया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस बिल को लेकर दो प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनके मुताबिक इस बिल को विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए ताकि उस पर विस्तार से चर्चा हो सके। जब तक यह बिल अंतिम रूप से पारित नहीं हो जाता, तब तक सभी निजी स्कूलों को 2024-25 की मौजूदा फीस संरचना पर ही बनाए रखने का आदेश दिया जाए। आतिशी ने कहा, हम इस बिल का सड़क से लेकर कोर्ट तक विरोध करेंगे। यह बिल न छात्रों के हित में है, न अभिभावकों के। इस मुद्दे पर आप विधायक संजीव झा ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बिल निजी स्कूलों द्वारा फीस में की गई बेतहाशा वृद्धि को कानूनी मान्यता देने की साजिश है। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार बनते ही स्कूलों ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ा दी और अब सरकार इस फैसले को वैध बनाने में जुटी है। वहीं तमिलनाडु के एक महिला सांसद से चेन स्नेचिंग के मामले में आतिशी ने कहा, दिल्ली के वीआईपी इलाके, एनडीएमसी क्षेत्र, जहां दिल्ली पुलिस, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार का नियंत्रण है, वहां एक सांसद तक सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा? उन्होंने कहा, पहले लोग कहते थे कि केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव होता है। अब जनता देख रही है कि जितने ज़्यादा इंजन होंगे।

ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया : रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन महादेव एक सैन्य अभियान नहीं, वह देश के हर परिवार के सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा सत्र में इन दोनों ऑपरेशन पर बधाई प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी सफलता ने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान-सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि विपक्ष और उसके नेताओं ने कभी भी देशहित की परवाह नहीं की और भारत की गरिमा को नीचा दिखाने के लिए

लगातार षडयंत्र किए। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की साख जनता के भरोसे पर रहती है। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर है, उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान-सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल और उसके नेता अपने स्वार्थों के चलते देशहित से लगातार दूर होते जा रहे हैं। इन्हें देश विरोधी ताकतों से प्यार है, जहां इनको अपना प्रतिबिंब दिखता है। भारत की प्रगति में भारत के आगे बढ़ने में यह लोग खुश नहीं हैं। ये चाहते हैं कि देश पिछड़ा रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हुई तो विपक्ष ने कई सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि भारत की सेनाएं आज भी उसी वीरता और निष्ठा से राष्ट्र की रक्षा कर रही हैं, जैसा उन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में किया था। लेकिन उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उन ऐतिहासिक सैन्य जीतों के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव क्यों दिखाया।

गेट बंद करने के लेकर हुए विवाद में युवक को मारी गोली, मौत

एजेंसी

नई दिल्ली। । दक्षिणी जिले के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के डेरा गांव में रात एक 37 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में मृतक की पहचान डेरा गांव निवासी संतलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि संतलाल की हत्या 19 वर्षीय युवक पीयूष यादव ने मामूली कहासुनी के बाद कर दी। पुलिस को देर रात करीब दो बजे सूचना मिली कि मोहल्ले में कुछ महिलाएं जोर-जोर से रो रही हैं। फतेहपुर बेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि संतलाल के सीने में गोली मार दी गई थी। घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद हुआ है। क्राइम टीम और रोहिणी की एफएसएल फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया में हत्या की वजह गेट बंद करने को लेकर हुए विवाद और आपसी टकराव को बताया जा रहा है। संतलाल जिस संपत्ति का केयरटेकर था, उसी के गेट को लेकर पीयूष यादव से उसकी कहासुनी हो गई थी। आरोपित पीयूष यादव, अमारा मोहल्ला, डेरा गांव का रहने वाला है और छतरपुर फेज-2 में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

धन्यवाद और हंगामे के बीच शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र धन्यवाद प्रस्ताव और हंगामे के बीच शुरू हो गया। दिल्ली विधानसभा को नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के माध्यम से समस्त कार्यवाही को डिजिटल करके पूर्णत पेपरलेस बनाने और सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का सत्ता और विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी (आआपा) के विधायकों ने प्रश्नकाल न होने पर सवाल उठाया। इसके साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर बधाई प्रस्ताव के दौरान आआपा विधायक संजीव झा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर संजीव झा की मांफी और शब्दों को वापस लेने की मांग की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संजीव झा को अपने शब्दों को वापस लेने को कहा, लेकिन वह नहीं मानें और आआपा विधायक हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने संजीव झा को मार्शल बुलाकर बाहर करने का आदेश दिया। इससे पहले

विधानसभा सत्र शुरू होने पर अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 07 मई को शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक रूप से निर्णायक और सफल रहा। भारत की सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य बनाते हुए उनको नेस्तनाबूत कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का बहुत कुशलता और संयम के साथ क्रियान्वयन हुआ, जिससे भारत की कुशल और मजबूत सैन्य क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। इस अभियान ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसी भी आतंकी कार्रवाई को सहन नहीं करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसी कड़ी में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकियों को श्रीनगर में मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे सदन की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस कार्रवाई में सम्मिलित सभी सेनाओं, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को हार्दिक बधाई दी।

एसआईआर पर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्षः प्रल्हाद जोशी

एजेंसी

नई दिल्ली। बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों को केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बेबुनियाद बताया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव के मतदाता पत्र प्रकरण को सनसनी फैलाने वाला करार दिया। बिहार एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है और संसद में चर्चा की मांग पर अड़ा है। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बातचीत में कहा, इन लोगों का चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग से विश्वास उठ गया है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ये आम लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट विवाद भी सुर्खियों में है। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस पर कहा, आप एक संवैधानिक नेता और विपक्ष हैं। फिर भी, आपके पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं। यहां, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं। वहीं, वे मतदाता सूची में नहीं होने का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब वे सिर्फ लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, तेजस्वी यादव का निशाना उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। उनके पास खुद दो मतदाता पहचान पत्र हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को बदनाम करने और सनसनी फैलाने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई की है। अब उन्हें चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, जब चुनाव आयोग ने दिखाया कि उनका नाम एक बार नहीं, बल्कि दो बार है। अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या दो जगहों पर नाम होना संवैधानिक है। क्या आप दो जगहों के मतदाता हो सकते हैं? अब चुनाव आयोग ने उन्हें आगे आने, दस्तावेज उपलब्ध कराने और स्पष्टीकरण देने को कहा है। ल्लेखनीय है कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। यहां पर एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में अपना नाम नहीं होने का दावा किया था।

दिल्ली विधानसभा में 1984 सिख दंगों पर सीएम रेखा गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा सत्र के दौरान 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। यह बयान उस समय आया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।कांग्रेस का दिल्ली विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कांग्रेस पर सिख विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सशस्त्र बलों को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा, मैं 1984 की बात भी करना चाहती हूं। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है। क्या उन्होंने उस कथन का असर नहीं समझा? उनके एक बयान ने देशभर में हजारों सिखों की हत्या करवाई और न जाने कितने घर तबाह हो गए। उस समय जिम्मेदारी कहां थी? रेखा गुप्ता ने कांग्रेस पर भारत

विभाजन और कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आपने (कांग्रेस) भारत को आजादी दिलाने का सारा श्रेय ले लिया, लेकिन जब कश्मीर, जो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, तब जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से पर कब्जा किया, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इससे पहले, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। वे दिल्ली में झुग्गियों के अवैध तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि भाजपा सरकार द्वारा 3,000 से अधिक झुग्गियों को तोड़ दिया गया, जिससे लगभग 15,000 परिवार बेघर हो गए।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस देवेंद्र यादव को हिरासत में लेकर सब्जी मंडी थाने ले गई। देवेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में बेघर हुए झुग्गीवासियों से मुलाकात की थी और उन्हें हरसंभव मदद और पुनर्वास का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही रेखा गुप्ता सरकार ने यह निर्णय लिया कि जब तक वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाएगा, तब तक झुग्गी बस्तियों को नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ता हर झुग्गी बस्ती में जाकर समर्थन जताएंगे और सरकार को गरीबों को बेघर करने से रोकेंगे।

सरकारी विज्ञापनों में पूर्व सीएम के नाम और पार्टी चिन्ह पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

एजेंसी

नई दिल्ली । तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापनों में जीवित व्यक्तियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, नेताओं या राजनीतिक पार्टी के प्रतीकों की छवियों का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के तमिलनाडु सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का उल्लेख करने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने इस मामले को इसी सप्ताह तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। रोहतगी ने कहा, यह एक अत्यंत आवश्यक और असामान्य मामला है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि राज्य सरकार की किसी भी योजना में मुख्यमंत्री या किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। हम (राज्य सरकार) किसी योजना का नाम क्यों नहीं रख सकते? ये योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा था कि वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीरें तो अनुमन्य हो सकती हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं में वैचारिक हस्तियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों या पार्टी के चिन्हों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध होगा। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ अन्नाद्रमुक सांसद सी. वी. षणमुगम की एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। षणमुगम ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं की ब्रांडिंग मुख्यमंत्री के नाम और तस्वीर के साथ-साथ पार्टी के पूर्व नेताओं और वैचारिक दिग्गजों की तस्वीरों के साथ करके सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।सरकारी विज्ञापनों की सामग्री को विनियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए क्रमिक निर्देशों और साथ ही भारत के चुनाव आयोग के 2014 के सरकारी विज्ञापन (सामग्री विनियमन) दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश में तमिलनाडु सरकार को कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विज्ञापनों में किसी भी जीवित राजनीतिक व्यक्ति का नाम, या किसी भी राजनीतिक दल के पूर्व मुख्यमंत्रियों या वैचारिक नेताओं की तस्वीरें शामिल करने पर रोक लगा दी गई।

संपादकीय

टैरिफ दादागिरी के बीच स्वदेशी एक जनक्रांति बने

वाराणसी में अपने लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे संकल्प लें कि अपने घर स्वदेशी सामान ही लाएंगे। उनका यह आह्वान न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की राजनीति और टैरिफ की दादागिरी का माकूल जबाव है बल्कि भारत को सशक्त अर्थ-व्यवस्था बनाने की बुनियाद भी है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान इसी सोच के साथ किया है। उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि भारत को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक गहन आर्थिक और सांस्कृतिक रणनीति है जो हमें बाहरी निर्भरता से मुक्त कर सकती है। यह वही आत्मनिर्भरता है, जिसका बीजारोपण महात्मा गांधी ने चरखे और खादी के माध्यम से किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वदेशी जागरण के माध्यम से कर रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का ही परिणाम है कि उन्होंने दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्थाह्व तक कह दिया, उनका यह कहना न केवल तथ्यहीन और निराधार है, बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता पर एक असभ्य एवं अक्षम्य आक्षेप भी है। इससे भी अधिक विडंबनापूर्ण और चिंताजनक बात यह है कि भारत के कुछ विपक्षी दलों ने इस अपमानजनक बयान को घरेलू राजनीति की ऑक्सीजन मानकर इसे आंतरिक राजनीति का हथियार बनाकर न केवल प्रचारित किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन भी किया। अक्सर विपक्षी दल देशविरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने में जुट जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का अंग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात के समय एकजुटता ही राष्ट्रवाद की पहचान होती है। यह वही देशविरोधी मानसिकता है जो विदेशी मंचों पर देश की छवि को चोट पहुंचाती है और राजनीतिक स्वार्थों एवं मतभेदों को राष्ट्रीय स्वाभिमान से ऊपर रखती है।

भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह ट्रंप ने मृतप्राय कहा, वह न केवल मौजूदा आर्थिक तथ्यों की अवहेलना है, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दबाने का एक रणनीतिक षडयंत्र भी है। आईएमएफ, विश्व बैंक और ओईसीडी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भी लगातार यह संकेत देती रही हैं कि भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी के बाद जिस गति से पुनरुत्थान किया है, वह अनेक विकसित देशों के लिए भी उदाहरण है। सच्चाई यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था न तो मृत है, न ही दिशाहीन। हां, चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आय असमानता, लेकिन इनसे जूझते हुए भारत आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत की वाणी अब कमजोर नहीं, बल्कि दृढ़ता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। ऐसे समय में जब अमेरिका जैसे देश एकतरफा फैसलों से वैश्विक व्यापार संतुलन को तोड़ने पर आमादा हैं, तब भारत को अपनी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मंत्र को एक संकल्प बनाकर व्यवहार में लाना होगा। अमेरिका हो या चीन, आर्थिक नीतियों में नैतिकता नहीं, स्वार्थ ही केंद्र में रहता है। इसीलिए भारत को अब यह समझना होगा कि केवल आयात पर निर्भर रहकर हम अपनी आर्थिक सुरक्षा नहीं कर सकते। जब तक हम उत्पादन, निर्माण और उपभोग के क्षेत्र में स्वदेशी विकल्प नहीं अपनाते, तब तक हम इस टैरिफ आतंकवाद और वैश्विक अस्थिरता के शिकार बने रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी जागरण मंच वर्षों से यह बात दोहराते रहे हैं कि भारत की आर्थिक समृद्धि का मूल मंत्र स्वदेशी है। यह विचार केवल देसी वस्तुओं के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है, स्वदेशी संसाधनों, तकनीकों, कौशल और संस्कृति के आधार पर विकास का रास्ता तय करना। भारत का आर्थिक इतिहास इसका साक्षी है कि जब-जब देश ने अपनी आंतरिक क्षमताओं पर विश्वास किया, तब-तब उसने वैश्विक मंच पर अपना प्रभुत्व सिद्ध किया। चाहे दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति हो, अंतरिक्ष में इसरो की सफलताएं हों या कोविड काल में स्वदेशी वैक्सीन बनाना, भारत ने दिखाया है कि वह किसी से कम नहीं। स्वदेशी का मंत्र सिर्फ यहां बनाएं तक सीमित नहीं है, यह यहां के लोगों द्वारा, यहां की सोच के साथ बनाया गया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया अभियान अब मेड बाय इंडिया की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भारत को ऐसी आर्थिक संरचना बनानी होगी जिसमें विदेशी पूंजी या तकनीक की बजाय स्वदेशी नवाचार, स्वदेशी उद्योग, और स्वदेशी उद्यमिता को बल मिले। इस संदर्भ में सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि जो नीतियां बनें, वे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हों, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लॉबी के दबाव में चलने वाली।

आज का समय वैसा ही है जैसा 1905 में बंग-भंग आंदोलन के समय था, जब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। आज फिर एक नई क्रांति की जरूरत है, लेकिन यह क्रांति फैक्ट्रियों में, बाजारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जाएगी। हमारे युवाओं को चाहिए कि वे स्टार्टअप, इनोवेशन और तकनीकी प्रयोगों में विदेशी नकल न करें, बल्कि भारतीय जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप नए समाधान विकसित करें। यही आत्मनिर्भर भारत की आत्मा है। हर

भारत में मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और चारा बेचना चाहता है अमेरिका

प्रमोद भार्गव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऊल-जलूल टैरिफ संबंधी घोषणाएं करके भारत पर बेवजह दबाव बनाने में लगे हैं। उन्होंने 1 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एकतरफा निर्णय ले लिया है। यही नहीं ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त जुमार्ना लगाने की बात भी कही है। यह टैरिफ देशी भारतीय दुग्ध एवं कृषि उत्पाद हड़पने की दृश्टि से भी लगाया गया है। जिससे भारत दबाव में आकर इन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल दे। लेकिन भारत भलि-भांति जानता है कि अमेरिका के सस्ते अनाज,पसु चारा और मांसाहारी चीज (पनीर) के लिए भारतीय बाजार खोल दिया जाता है तो किसान तो तबाह होगा ही शाकाहारी संस्कृति को भी पलीता लगेगा। साथ ही भारत सरकार जिन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को बढ़ावा देकर कृषि और दूध उत्पादों को वैश्विक बाजार में लाने की पृश्ठभूमि तैयार कर रही है, वह विचार भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए सरकार ने साफ कह दिया है कि इन क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। वैसे भी अब यह सच्चाई सामने आ रही है कि एकतरफा वैश्वीकरण से दुनिया का भला होने वाला नहीं है। अतएव स्वदेशी उत्पादों के जरिए ही आत्मनिर्भर बने रहने की पहल जारी रखनी होगी। भारत इस दिशा में मजबूती से बढ़ भी रहा है। इसलिए ट्रंप जैसे वाचाल और सनकी शासक की परवाह करने की जरूरत नहीं है।

भारत में गाय को माता यूं ही नहीं कहा जाता है। वे भारतीय ऋषि ही थे, जिन्होंने सबसे पहले जाना था कि गाय के दूध में ऐसे पोषक तत्व हैं, जो शरीर और दिमाग दोनों को ही स्वस्थ रखते हैं। यह दूध ही है, जिससे दही, मठा, मक्खन और घी जैसे सह-उत्पाद निकलते हैं। ये उत्पाद मिठाई की दुकानों से लेकर डेयरी उद्योग के जरिए करोड़ों लोगों के रोजगार का मजबूत मध्ययम बने हुए हैं। लंबे समय तक गाय से पैदा बैल पर ही भारतीय कृषि निर्भर रही है। इसी कृषि की जीडीपी में 24 प्रतिशत की भागीदारी है। भारतीय दुग्ध उत्पादन से लेकर दूध पीने में दुनिया में पहले स्थान पर हैं। इसी दूध पर अमेरिकी बाजार के कब्जे के लिए अमेरिका अपने यहां उत्पादित मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और पशु चारा बेचना चाहता है। अन्य यूरोपीय देशों की निगाह भी इस दूध के व्यापार पर भी टिकी हैं। इस बाबत अमेरिका और भारत के बीच 500 बिलियन डॉलर के व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इसी समझौते की सूची में अमेरिकन मांसाहारी दूध के उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार ने इस बाबत दो टूक कह दिया है कि अमेरिकी दुग्ध उत्पादों और पशु चारे को भारतीय बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। यह हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका और उनकी संस्कृति की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा प्रश्न है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

दरअसल अमेरिका मांसयुक्तचीज (पनीर)और पनीर भारत में बेचने का इच्छुक है। इस चीज को बनाने की प्रक्रिया में बछड़े की आंत से बने एक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। अत्यंत घिनौना कृत्य करके इसे चीज में मिलाया जाता है। शाकाहारी लोग इस प्रक्रिया को देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए भारत के शाकाहारियों के लिए यह पनीर वर्जित है। गौ-सेवक व गऊ को मां मानने वाला भारतीय समाज इसे स्वीकार नहीं करता। अमेरिका में गायों को मांसयुक्त चारा खिलाया जाता है, जिससे वे ज्यादा दूध दें। हमारे यहां गाय-भैंसें भले ही कूड़े-कचरे में मुंह मारती फिरती हों, लेकिन दुधारू पशुओं को मांस खिलाने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता ? लिहाजा अमेरिका को चीज बेचने की इजाजत नहीं मिल पा रही है।

भारत में 13 जनवरी 1970 को फ्लड ऑपरेशन के साथ दूध का उत्पादन शुरू हुआ था। इसे ही श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। यह केवल भारत में ही नहीं विश्व में सबसे बड़े ग्रामीण कार्यक्रमों में से एक है। इसी की बदौलत भारतीय डेयरी उद्योग का चेहरा बदला और लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों की आर्थिकी में क्रांतिकारी बदलाव आया। दरअसल फिरंगी हुकूमत के दौरान पॉल्सन नाम की ब्रिटिश कंपनी का इस क्षेत्र का दूध खरीदने पर एकाधिकार था। कंपनी दुग्ध उत्पादकों का लगातार शोषण कर रही थी। इस शोषण की शिकायत किसानों ने सरदार पटेल से की। पटेल गोधन, गोरस और गोदान की हिंदू जीवन शैली के अनुयायी थे। पटेल शोषण की जानकारी से बेचैन हुए और लौहपुरुष के अवतार में आ गए, उन्होंने तत्काल कंपनी को दूध बेचने से मना कर दिया। उनका मानना था कि जब कंपनी को दूध मिलेगा ही नहीं, तो उसे किसानों की शर्तें मानने को मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही पटेल ने सभी किसानों को मिलकर सहकारी संस्था बनाकर स्वयं दूध और दूध के उत्पाद बेचने की सलाह दी। पटेल के इस सुझाव से किसान सहमत हो गए और अंग्रेजों को दूध न देने की चुनौती दे दी। बाद में 1946 में पटेल ने अपने भरोसे के साथ ही मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल की सहायता से भारत की पहली दुग्ध सहकारी संस्था की स्थापना की, इसे ही बाद में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के नाम से जाना गया। 250 लीटर दूध का प्रतिदिन कारोबार करने वाली इसी संस्था को आज विश्वव्यापी संस्था ह्यअमूलह्य के नाम से जाना जाता है। मिशिगन स्टेट विवि से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके भारत लौटे वर्गीज कुरियन ने सरकारी नौकरी छोड़कर इस संस्था में काम शुरू किया और भारत का पहला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। इसके बाद किसानों की ज्ञान परंपरा और कुरियन के यांत्रिक गठबंधन से इस संस्था ने उपलब्धि का शिखर चूम लिया।

बिना किसी सरकारी मदद के बूते देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से न केवल वे बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में सफल हैं, बल्कि इसके सह-उत्पाद दही, मठा, घी, मक्खन, पनीर, मावा आदि बनाने में भी मर्मज्ञ हैं। दूध का 30 फीसदी कारोबार संगठित ढांचा, मसलन डेयरियों के माध्यम से होता है। देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हैं। 14 राज्यों की अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं। देश में कुल कृषि खाद्य उत्पादों व दूध से जुड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं महज दो फीसदी हैं, किंतु वह दूध ही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रसंस्करण करके दही, मठा, घी, मक्खन, मावा, पनीर आदि बनाए जाते हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे आठ करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। करीब 1.5 करोड़ परिवार सहकारी दुग्ध उत्पादकता से जुड़े हैं, जबकि 6.5 करोड़ ग्रामीण परिवार आज भी सहकारिता के दायरे से वंचित हैं। दूध उत्पादन में ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। रोजाना दो लाख से भी अधिक गांवों से दूध एकत्रित करके डेयरियों में पहुंचाया जाता है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सीधे शहरी एवं कस्बाई ग्राहकों तक भी दूध बेचने का काम करते हैं।

इसी दूध के बाजार को अमेरिका हड़पना चाहता है। जबकि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुछ माह पहले ही दस हजार नई कृषि सहकारी समितियों को हरी झंडी दिखाई है। अगले पांच साल में इनकी संख्या दो लाख तक पहुंचाने की है। इन्हीं सहकारी संस्थाओं के जरिए कृषि और दुग्ध उत्पादों को भारत से लेकर एशिया और यूरोप तक बाजार में पहुंचाने की है। ऐसे में यदि अमेरिकी दुग्ध उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए जाते हैं तो इन समितियों की मुश्किलें तो बढेंगी ही, दुग्ध उत्पादक आठ करोड़ दूधियों की आजीविका पर भी संकट के बादल गहरा जाएंगे।

दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के अमर नायक का युगांत

अजय कुमार

झारखंड की धरती का वो सूरज, जिसने आदिवासी समाज को शोषण, सूदखोरी और अन्याय के अंधेरे से निकालकर स्वाभिमान और सम्मान की रोशनी दिखाई, आज सदा के लिए अस्त हो गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिन्हें झारखंड का पथ प्रदर्शक कहा जाता था, ने 4 अगस्त 2025 को सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। 81 वर्ष की आयु में उनके निधन ने न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश को एक ऐसी शख्सियत से वंचित कर दिया, जिसने जंगलों से लेकर संसद तक आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। शिबू सोरेन एक नेता से कहीं अधिक थे वे एक क्रांति थे, जिन्होंने महाजनों, जमींदारों और शोषक व्यवस्था के खिलाफ उलगुलान की हुंकार भरी। उनकी मशाल ने लाखों आदिवासियों को नई राह दिखाई, और उनकी डुगडुगी की गूंज आज भी झारखंड की माटी में गूंजती है।

11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और समर्पण की गाथा है। उनके पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक और गांधीवादी विचारों के व्यक्ति थे, जो उस दौर में महाजनों के आतंक के खिलाफ आवाज उठाते थे। उस समय झारखंड में आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प ली जाती थीं। मेहनत का फल महाजन छीन लेते थे, और आदिवासी समाज गरीबी और शोषण का शिकार था। 27 नवंबर 1957 को सोबरन सोरेन की हत्या ने शिबू के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने शोषण के खिलाफ बगावत का रास्ता चुना। युवा शिबू ने आदिवासी युवाओं को संगठित करना शुरू किया, और यहीं से दिशोम गुरु की यात्रा शुरू हुई, जिसने झारखंड के इतिहास को नया मोड़ दिया।

1970 के दशक में शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन की शुरूआत की, जो झारखंड के आदिवासी आंदोलन का स्वर्णिम अध्याय बन गया। इस आंदोलन में आदिवासी युवा तीर-कमान लेकर खेतों की रखवाली करते, और महिलाएं हंसिया लेकर महाजनों की फसल काट लेती थीं। मांदर की थाप पर मुनादी के साथ यह आंदोलन रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, टुंडी, पलमा, तोपचांची और बेरमो जैसे इलाकों में फैल गया। शिबू ने एक नैतिक मयार्दा तय की यह लड़ाई केवल खेतों तक सीमित रहेगी, न महाजनों की महिलाओं को निशाना बनाया

जाएगा, न उनकी अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस अनुशासन ने उनके आंदोलन को न केवल मजबूती दी, बल्कि आदिवासियों में आत्मविश्वास और एकता का संचार किया। धनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को आदिवासियों का नायक बना दिया, जो शोषण और सूदखोरी से मुक्ति का प्रतीक बन गए।

4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन ने बिनोद बिहारी महतो और कॉमरेड एके राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की स्थापना की। यह संगठन बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से प्रेरित था, जिसने 1971 में स्वतंत्रता हासिल की थी। झामुमो का लक्ष्य था झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाना और आदिवासी समाज को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करना। इस संगठन ने न केवल आदिवासियों को एकजुट किया, बल्कि उनकी आवाज को राष्ट्रीय पटल पर बुलंद किया। शिबू की अगुवाई में झामुमो ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी, और 2000 में झारखंड के गठन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही। आज झामुमो झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है, जो शिबू के सपनों को जीवित रखती है।

शिबू सोरेन का जीवन आसान नहीं था। पारसनाथ के घने जंगलों में भटकते हुए, पुलिस की गोलियों से बचते हुए, उन्होंने रातें पेड़ों की छांव में गुजारीं। 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। धनबाद के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर केबी सक्सेना ने उन्हें सरेंडर के लिए राजी किया। 1976 में धनबाद जेल में बंद शिबू ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। एक महिला कैदी के छठ गीत सुनकर वे भावुक हो गए और जेल में छठ पूजा का आयोजन करवाया। कैदियों ने एक समय का भोजन त्यागकर इसका खर्च जुटाया, और महिला ने पारंपरिक आस्था के साथ पूजा की। यह घटना उनकी मानवीयता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक हैएक अन्य घटना में, पलमा के जंगल में रात के समय पुलिस ने उन्हें घेर लिया। डुगडुगी की आवाज पर आदिवासियों का हुजूम इकट्ठा हो गया, और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। यह था शिबू सोरेन का जनता के साथ अटूट रिश्ता। उनकी डुगडुगी एक संकेत थी, जो आदिवासियों को एकजुट करने की ताकत रखती थी।

शिबू सोरेन सामाजिक न्याय और महिला सम्मान के प्रति बेहद सजग थे। एक बार दुमका से धनबाद लौटते वक्त, छेड़खानी के एक मामले को सुनकर उन्होंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और गांव में कचहरी लगाकर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया। शराब के खिलाफ उनकी सख्ती भी उल्लेखनीय थी। एक बार अपने चाचा के शराब पीने पर वे इतने नाराज हुए कि उन्हें पीटने पर उतारू हो गए। उनकी यह नैतिकता और अनुशासन उन्हें एक अलग पहचान देता था। वे न केवल आदिवासियों के नेता थे, बल्कि सामाजिक मूल्यों के रक्षक भी थे।

शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। 1980 में वे पहली बार दुमका से लोकसभा सांसद बने। 1989, 1991 और 1996 में भी वे लोकसभा पहुंचे। 2002 में वे राज्यसभा सांसद बने, और उसी साल दुमका से लोकसभा उपचुनाव जीता। वे तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे 2005 में 10 दिन के लिए, 2008-09 और 2009-10 में। केंद्र में कोयला मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी राजनीति विवादों से भी घिरी रही, लेकिन आदिवासियों के प्रति उनकी निष्ठा कभी कम नहीं हुई। उनकी विरासत उनके बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाली है, जिनके नेतृत्व में झामुमो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनी।

शिबू सोरेन के निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भावुक होकर कहा, ह्लआज मैं शून्य हो गया हूँ। मेरे पिता दिशोम गुरु झारखंड के सपनों का प्रतीक थेह्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ह्लशिबू सोरेन जी का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका योगदान आदिवासी सशक्तिकरण और झारखंड आंदोलन में हमेशा याद रखा जाएगाह्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ह्लदिशोम गुरु ने शोषितों की आवाज बुलंद की। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगीह्व झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे, मांदर की थाप पर शोक गीत गाए गए, और उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभाएँ आयोजित की गईं। सोशल मीडिया पर आम जनता, सामाजिक कार्यकताओं और नेताओं ने उन्हें याद किया। एक यूजर ने लिखा, ह्लशिबू सोरेन ने हमें सिखाया कि हिम्मत और एकता से कोई भी जंग जीती जा सकती है।

किन लोगों को हार्ट चेकअप जरूर कराना चाहिए? एक्सपर्ट से जानें

हार्ट हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जो खून को पंप करता है और ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है. जब हार्ट स्वस्थ होता है, तो शरीर की बाकी सभी क्रियाएं बेहतर ढंग से चलती हैं. लेकिन जब हार्ट की सेहत कमजोर होने लगती है, तो इसके लक्षण तुरंत नजर नहीं आते, जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता है. यही कारण है कि हार्ट हेल्थ को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस, गलत खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से हार्ट डिजीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. इसलिए हर व्यक्ति को न सिर्फ अपने हार्ट की देखभाल करनी चाहिए, बल्कि समय-समय पर जांच भी करानी चाहिए ताकि कोई जोखिम समय रहते पकड़ा जा सके(हार्ट को कई चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे ज्यादा फैट और नमक वाला खाना, धूम्रपान, शराब, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और तनाव. ये सभी चीजें धीरे-धीरे हार्ट की नसों को सिकोड़ सकती हैं यानी संकरा बना सकती हैं, जिससे ब्लड फ्लो धीमाहोजाताहै. जब हार्ट तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, और हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हार्ट में ब्लॉकेज की वजह बन सकता है. हार्ट में खराबी आने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि सांस फूलना, सीने में दर्द, थकान, हाथ-पैरों में सूजन या चक्कर आना. अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया गया, तो स्थिति गंभीर हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों से बचा जाए और स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाई जाए.

किन लोगों को हार्ट चेकअप जरूर कराना चाहिए?

दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में डॉ अजीत जैन बताते हैं किहर किसी के लिए हार्ट की जांच फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए यह और भी जरूरी हो जाती है. 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को साल में एक बार हार्ट चेकअप जरूर कराना चाहिए, भले ही कोई लक्षण न हों.

जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या मोटापा है, उनके लिए समय-समय पर जांच कराना और भी आवश्यक है. इसके अलावा जिनके परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है जैसे माता-पिता या भाई-बहनों को हार्ट की बीमारी रही हो, उन्हें और अधिक सतर्क रहना चाहिए. स्मोकिंग और अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले लोगों को भी समय-समय पर हार्ट टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये आदतें हार्ट पर सीधा असर डालती हैं.

ध्वस्त हुआ एक और झूठा नैरेटिव

सुरेश हिंदुस्तानी

भारत में स्वार्थी राजनीति का खेल यूँ तो बहुत पुराना है, लेकिन ऐसी राजनीति जनमानस को केवल भ्रमित करने का काम ही करती है। यह भी सत्य है कि इसका प्रभाव लम्बे समय तक नहीं रहता। राजनीति सच की होना चाहिए, न कि झूंठ की। लेकिन आज विसंगति यह है कि राजनीतिक दल केवल अपने लिए ही राजनीति करते हैं, देश के लिए नहीं। आज राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करने तक सीमित हो गया है। ऐसी ही राजनीति के माध्यम से हिन्दू आतंकवाद की थ्योरी स्थापित करने का खेल खेला गया। अब इस षड्यंत्र की परतें भी उधड़ने लगी हैं। जिसके फलस्वरूप फेक नैरेटिव का पदार्फास हो गया।

भारत क्या है और उसकी विरासत क्या है? इसके मूल में जो प्रमाण मिलते वे उसका एक दर्शन है। यह दर्शन मात्र कुछ वर्षों का कार्य नहीं, बल्कि एक लम्बी साधना के बाद निकला है। जो भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणीय पाथेय है। लेकिन लम्बे समय से इस आदर्श विरासत को मिटाने का कुचक्र भी चल रहा है। हम यह भली भांति जानते हैं कि जब जब भारतीय समाज विघटित हुआ है, तब भारत को कमजोर करने के सुनियोजित प्रयास भी किए। देश विघातक शक्तियों ने भारत के समाज में फूट डालकर अपने मंसूबों को सफल किया। ऐसे प्रयास आज भी हो रहे हैं। मूल समस्या पर किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं हो रहा है, और न ही उस दिशा में कोई प्रयास ही हो रहा है।

अभी अभी न्यायालय ने मालेगाँव विस्फोट मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जिसमें हिन्दू आतंकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त किया गया। इस नैरेटिव की भूमिका पूरी तरह से आधारहीन ही थी। न्यायालय के निर्णय से यह ज्ञात हुआ कि इसमें जिनको आरोपी बनाया गया, उनके विरोध में पर्याप्त प्रमाण नहीं थे, जब प्रमाण ही नहीं थे, तब इस मामले में गिरफ्तार करने की जल्दबाजी किसके संकेत पर की गई। यह बहुत बड़ा षड़यंत्र ही था, जिसकी कलई धीरे धीरे खुलने लगी हैं। एक पूर्व अधिकारी का बयान इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। हिन्दू समाज को बदनाम करने का यह षड्यंत्र केवल एक वर्ग को खुश करने प्रयास मात्र ही था। राजनीतिक दलों को हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति मात्र देश को शक्तिशाली और समाज को संगठित करने के लिए होना चाहिए। यहां एक सवाल खड़ा करना मुझे बहुत आवश्यक लग रहा है। क्या देश के लिए काम करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही होती है? विपक्ष और समाज की भी होती है। अगर सभी एक भाव से समाज को एक करने का कार्य करें तो भारत का सूर्य केवल भारत को ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को आलोकित करेगा, यह तय है।

मालेगाँव विस्फोट मामले में षड्यंत्र की बुनियाद किसने की, इस सवाल का उत्तर पहले से वातावरण में तैर रहा था। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हिन्दू आतंकवाद की झूठी कहानी की पटकथा तैयार की।

अब सवाल यह उठता है कि रामराज्य की संकल्पना को जमीन पर उतारने का सपना देखने वाले महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने हिन्दू आतंकवाद का प्रपंच रचा। इसका पहला कारण तो यही समझ में आता है कि यह सब एक विशेष वर्ग को खुश करने का प्रयास मात्र ही था। कांग्रेस की ऐसी राजनीति करने वाले एक प्रकार से कांग्रेस को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमें यह भी याद होगा कि एक बार कांग्रेस की सरकार के समय भगवान श्रीराम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया गया। उस समय हिन्दू समाज की जाग्रति के समक्ष कांग्रेस को झुकना पड़ा और सरकारी स्तर पर किए गए प्रयास पर पूरी तरह से पानी फिर गया।

मालेगाँव विस्फोट मामले में भी ऐसा ही प्रयास किया गया। इसका एक कारण कांग्रेस की वह मानसिकता है, जिसके तहत कांग्रेस को नेतृत्व देने वाले राजनेता केवल यही सोचते हैं कि हम तो सरकार चलाने के लिए ही बने हैं।

रूस से तेल खरीद पर ट्रंप की भारत को चेतावनी, कहा- और बढ़ाएंगे टैरिफ

एजेंसी
वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क (टैरिफ) और बढ़ाने की धमकी दी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने रूस से तेल खरीद और उसके कथित पुनः विक्रय को लेकर भारत पर और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ट्रंप ने सोमवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए कहा, भारत न केवल बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। उन्हें परवाह नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अमेरिका भारत पर लगने वाले टैरिफ को 'काफी बढ़ाएगा'। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि टैरिफ में कितनी वृद्धि की जाएगी। उल्लेनखीय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 01 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था। इस टैरिफ को उन्होंने रूस से भारत के रक्षा और ऊर्जा आयात से जोड़ते हुए अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।

लिथुआनिया के वित्त मंत्री रिमंतास सादजियस बने देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री

विलनियस। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानस नौसेदा ने प्रधानमंत्री गिंटौटस पलुक्कास के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री रिमंतास सादजियस को नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अपनी साली की कंपनी के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों को लेकर दबाव के बीच वह पद छोड़ देंगे। नौसेदा ने अपने कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक आदेश में कहा, मैं रिमंतास सादज़ियस को नई सरकार के गठन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का निर्देश देता हूं। 64 वर्षीय सादजियस पिछले साल दिसंबर से लिथुआनिया के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे दो बार इस पद पर रह चुके हैं- पहली बार 2007 से 2008 और फिर 2012 से 2016 तक। इसके अतिरिक्त, वे 2016 से 2025 तक यूरोपीय लेखा न्यायालय के सदस्य भी रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, पालुक्सास की पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स इस सप्ताह के अंत तक नए स्थायी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि, किसी भी नए प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत साबित करना होगा, जो फिलहाल एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। सोशल डेमोक्रेट्स के पास अकेले बहुमत नहीं है और उन्हें फॉर लिथुआनिया (सेंटर-लेफ्ट) और नेमुनास डॉन (लोकप्रियतावादी) जैसे गठबंधन सहयोगियों का समर्थन हासिल करना होगा, जो अक्सर आपस में मतभेद रखते हैं।

ट्रंप की चेतावनियों के बीच रूस का नरम रुख, जेलेंस्की से मिलने को तैयार हुए पुतिन

मॉस्को/कीव। यूक्रेन में फरवरी, 2022 से जारी युद्ध को लेकर एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से सीधी मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस संबंध में संकेत देते हुए कहा कि विशेषज्ञ स्तर पर तैयारियां पूरी होते ही पुतिन जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्धविराम के लिए रूस पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि अगर रूस युद्ध नहीं रोकता तो अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था पर और भी सख्त प्रतिबंध लगाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले से ही पुतिन के साथ ट्रंप की मौजूदगी में सीधी बातचीत की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि आमने-सामने की बातचीत से ही उन्हें एक वैध नेता के तौर पर मान्यता मिलेगी और समाधान की ठोस राह खुलेगी। अब जब पुतिन की ओर से सहमति के संकेत मिले हैं, तो यह युद्धविराम और संभावित शांति वार्ता की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस की ओर से नरम संकेत तो मिले हैं, लेकिन पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूक्रेन पर हमले की जिन मूल मांगों के आधार पर युद्ध शुरू हुआ था, वह अब भी कायम हैं। इसका मतलब है कि रूस की ओर से शांति वार्ता की सहमति के बावजूद कई मुद्दों पर टकराव बना रह सकता है।

जापान में पूर्व पीएम आबे के सहयोगी कोइची हागिउदा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

टोक्यो। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की नीति अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष कोइची हागिउदा को दान के रूप में मिले पैसे में हेराफेरी के आरोप का सामना करने का रास्ता साफ हो गया। टोक्यो जिला लोक अभियोजक कार्यालय ने अपने पिछले फैसले को पलटते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जापान के अखबार द असाही शिंबुन के अनुसार एलडीपी के इस सहयोगी पर पार्टी के दूसरे गुट से प्राप्त 22.9 मिलियन येन के दान को दर्ज न करने का संदेह है। चार साल में प्राप्त राजनीतिक चंदा, आय और व्यय की रिपोर्ट की जांच में यह संदेह और पुख्ता हुआ है। अभियोजकों का मानना है कि कोइची हागिउदा ने राजनीतिक धन नियंत्रण कानून का उल्लंघन किया है। अभियोजकों ने कानूनी प्रक्रिया के प्रारूप में जुर्माना जैसे दंड का प्रावधान किया है। इसमें कहा गया है कि अगर हागिउदा इसके लिए तैयार नहीं होते तो खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाए। असाही शिंबुन के अनुसार हागिउदा एलडीपी के सबसे बड़े गुट का हिस्सा रहे हैं।

बलूचिस्तान के केच में जंगयान बलूच के घर पर हमला

एजेंसी
क्वेटा (बलूचिस्तान)। पाकिस्तान समर्थित भाड़े के हत्यारों (मौत दस्ता) ने सोमवार रात केच जिले में थिसिल टेम्प के तेलकान क्षेत्र में जंगयान बलूच के घर पर हमला किया। हमले में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जंगयान के घर पर इससे पहले भी कई बार हमला किया जा चुका है। द बलूचिस्तान पोस्ट की बलूची भाषा की समाचार सेवा की खबर के अनुसार, एक स्थानीय संवाददाता ने सूचित किया है कि यह हमला रात में हुआ, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जंगयान बलूच के घर पर पहले भी कई बार हमला हो चुका है। बलूचिस्तान में मौत दस्तों और पाकिस्तान समर्थित संस्थाओं पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। इन आरोपों में जबरन अपहरण, न्यायेतर हत्याएं और

नागरिकों को निशाना बनाना शामिल हैं। इस बीच द बलूचिस्तान पोस्ट की अंग्रेजी भाषा की समाचार सेवा की खबर के अनुसार, एक दशक से भी अधिक समय से लापता अमीर बख्श बलूच के परिवार ने कराची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर संघीय सरकार से उनके ठिकाने का खुलासा करने और अगर कोई आरोप है तो उन्हें अदालत में पेश करने की अपील की है। इस दौरान केंद्रीय बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) की नेता सम्मी दीन बलूच भी मौजूद थीं। अमीर बख्श की बेटी सदाफ बलूच ने कहा कि उनके पिता को 4 अगस्त 2014 को ग्वादर के अंबी बाजार कुलांच इलाके से सुरक्षा बल जबरन उठा ले गए थे। ग्यारह साल बीत चुके हैं। अभी भी नहीं पता कि वह कहां हैं या जिंदा भी हैं या नहीं। सदाफ ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का गायब होना नहीं है, यह पूरे परिवार की निरंतर पीड़ा, मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक मृत्यु है। सदाफ बलूच ने कहा कि पिता को ढूंढ़ने के लिए उसने परिवार के साथ सभी कानूनी और शांतिपूर्ण रास्ते अपना लिए हैं। परिवार को सब जगह से निराशा ही हाथ लगी है। सदाफ ने संघीय सरकार, न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मानवाधिकार संगठनों से अपील करते हुए कहा कि यह किसी राजनीतिक आंदोलन की मांग नहीं है। यह एक बेटी की गुहार है।

तूफान फ्लोरिस का कहर : ब्रिटेन और आयरलैंड में यातायात एवं बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित

एजेंसी
लंदन/डबलिन। तूफान फ्लोरिस ने ब्रिटेन और आयरलैंड के कई हिस्सों में व्यापक तबाही मचाई है। स्कॉटलैंड में रेल सेवाएं बुरी तरह बाधित हुई हैं, जबकि आयरलैंड में हजारों घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है नेटवर्क रेल ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि स्कॉटलैंड में रेल नेटवर्क पर तूफान का असर जारी रह सकता है, क्योंकि सड़कों और पटरियों पर गिरे पेड़ों और मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है। हालांकि काफी हद तक रास्ते साफ किए जा चुके हैं, लेकिन मंगलवार सुबह अंतिम सुरक्षा जांच के बाद ही सेवाएं पूरी तरह बहाल की जा सकेंगी। वहीं आयरलैंड में करीब 2700 घरों, फार्महाउस और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली नहीं है, जिसकी पुष्टि ईएसबी नेटवर्क्स ने की है। कंपनी के मुताबिक, उनकी टीमें देर रात तक बिजली बहाल करने का प्रयास कर रही हैं और अधिकांश उपभोक्ताओं को आज रात तक सेवा बहाल होने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, ÷हम इस असुविधा के लिए सभी प्रभावित घरों, फार्मों और व्यवसायों से क्षमा मांगते हैं। बिजली कटौती और बहाली की जानकारी के लिए उपभोक्ता पॉवर चेक डॉट आईई वेबसाइट पर रीयल-टाइम अपडेट देख सकते हैं।तूफान फ्लोरिस के कारण कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे पेड़ उखड़ गए, आधारभूत ढांचे को नुकसान हुआ और यात्रा बेहद जोखिम भरी हो गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और यात्रा से पहले ताजा अपडेट जरूर लें।

टेक्सास के 50 से ज्यादा डेमोक्रेट्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

एजेंसी
ऑस्टिन (टेक्सास)। रिपब्लिकन हाउस स्पीकर डस्टिन बरोज ने 50 से ज्यादा डेमोक्रेट्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सदन में इनके अनुपस्थित न रहने से कोरम पूरा नहीं हो सका। इसलिए कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की संख्या बढ़ाने का मंसूबा पूरा नहीं हो सका। ऑस्टिन अमेरिकन-स्टेट्समैन की खबर के अनुसार, बरोज ने सदन में कहा, वे राज्य छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से भी मुंह मोड़ लिया जिनका प्रतिनिधित्व करने की उन्होंने शपथ ली थी। वे राज्य के बाहर के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। इसके तुरंत बाद गवर्नर ग्रेग एबॉट ने टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि ऐसे किसी भी सदस्य का पता लगाएं, उसे गिरफ्तार करें और सदन के कक्ष में वापस लाएं। यह वारंट कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सदन में अनुपस्थित

पाए गए सदस्यों को वापस बुलाने के लिए बाध्य करते हैं। बावजूद इसके कोरम भंग करने पर उनकी आपराधिक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह वारंट अधिकारियों को राज्य से बाहर जाकर उन दर्जनों डेमोक्रेट्स को वापस लाने का अधिकार नहीं देते जो सदन को आवश्यक कोरम से वंचित करने के लिए इलिनॉय (न्यूयॉर्क) और मैसाचुसेट्स चले गए। सदन के 62 डेमोक्रेटिक सदस्यों में से केवल छह ही सात मिनट तक सत्र में उपस्थित रहे। लुबॉक से रिपब्लिकन उम्मीदवार बरोज ने सदन को बताया कि जल्द ही मतदान करवा कर पुनर्वितरण योजना को मंजूरी दिलाई जाएगी। यही बात उन्होंने संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में दोहराई।

यमन नौका त्रासदी, सिर्फ 12 यात्रियों को बचाया जा सका, 142 की मौत

एजेंसी
सना (यमन)। यमन के तट पर रविवार को पलटी नाव में सवार 154 प्रवासियों में से सिर्फ 12 को बचाया जा सका है। बाकी 142 यात्रियों की मौत हो गई। यह सभी इथियोपिया के रहने वाले हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के प्रमुख अब्दुसत्तोर एसोव ने यह जानकारी दी। फ्रांस के ल्योन से संचालित 'अफ्रीकान्यूज' समाचार चैनल की खबर के अनुसार, एसोव ने बताया कि अदन की खाड़ी में हुई इस त्रासदी में केवल 12 लोगों को बचाया जा सका, जबकि शेष 142 यात्रियों को मृत मान लिया गया है। अब तक 68 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर पश्चिमी यमन के खानफा तट पर पाए गए। अबयान सुरक्षा निदेशालय ने बयान में त्रासदी को देखते हुए वृह्द खोज और बचाव अभियान चलाया गया। संयुक्त प्रवासन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल हजारों प्रवासी (इनमें ज्यादातर इथियोपियाई होते हैं) अफ्रीका के हॉर्न से लाल सागर

पार कर यमन से होते हुए अमीर खाड़ी देशों में काम की तलाश में जाते हैं। सर्वाधिक यात्रा किया जाने वाले इस मार्ग को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी साल मार्च में जिबूती और यमन के बीच समुद्र में चार नावों के पलट जाने से 186 अफ्रीकी लापता हो गए थे। इस लिहाज से 2024 दुखदायी रहा। इस साल 550 प्रवासियों की मौत हो गई थी। संयुक्त प्रवासन केंद्र ने कहा कि यमन में चल रहे गृहयुद्ध ने प्रवासियों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

बीएलए और बीएलएफ का दावा, लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना के वाहन फूंके

एजेंसी
इस्लामाबाद। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दो सशस्त्र समूहों बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों, आपूर्ति काफिलों और संसाधन परिवहन वाहनों को निशाना बनाकर किए गए पांच से अधिक हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह हमले जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में किए गए। लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के कई वाहनों को फूंक दिया। द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बीएलए प्रवक्ता जीयंद बलूच ने जारी बयान में दावा किया कि समूह के लड़ाकों ने जमुरान, धादर और मस्तुंग जिलों में सैन्य चौकियों, आपूर्ति वाहनों और खनिज परिवहन ट्रकों को निशाना बनाकर पांच स्थानों पर हमला किया। लड़ाकों ने रविवार को जमुरान के जबशान इलाके में पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों पर रिमोट-नियंत्रित

आईईडी हमला किया। हमले में दो सैनिक घायल हो गए। दोनों सैनिक अपनी चौकी पर पानी ले जा रहे थे। सशस्त्र समूह ने कहा कि लड़ाकों ने धादर के सुन्नी शोरान इलाके में मुख्य सैन्य शिविर के द्वार पर तैनात कर्मियों को भी निशाना बनाया। हमले में कई लोग हताहत हुए। बीएलए ने दावा किया कि हमले के बाद, सेना ने आस-पास के नागरिक इलाकों पर मोर्टार के गोले दागे। बीएलए ने कहा कि लड़ाकों ने मस्तुंग के गुलाम परांज में बलूच के राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन में शामिल दो वाहनों पर हमला किया और चेतावनी जारी करने के बाद ड्राइवरों को छोड़ दिया। समूह ने कहा कि उसने मस्तुंग के स्पिलिंजी के माराओ इलाके में पाकिस्तान की सेना के लिए राशन ले जा रहे दो ट्रकों को जब्त कर लिया और तिगरान के अब्दोई में एक अन्य आपूर्ति ट्रक को नष्ट कर दिया। जीयंद बलूच ने सभी ट्रांसपोर्टरों को सेना के लिए आपूर्ति या खनिजों का परिवहन बंद करने की चेतावनी दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पहली अगस्त को ग्वादर के कुंडासोल के सब्जकी इलाके में पाकिस्तान के एक सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलूच के अनुसार, लड़ाकों ने शिविर को निशाना बनाकर कई मोर्टार गोले दागे। गोले शिविर के अंदर गिरे और भारी जनहानि हुई।

यूक्रेन में ड्रोन खरीद घोटाला : सांसद, पूर्व गवर्नर समेत 6 लोगों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज

एजेंसी
कीव। यूक्रेन में सैन्य ड्रोन और जैमिंग उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस मामले में एक सांसद, एक पूर्व गवर्नर, एक सैन्य अधिकारी सहित कुल छह लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धन की हेराफेरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह जानकारी यूक्रेन की भ्रष्टाचार-निरोधी एजेंसी ने दी। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एनएबीयू) के अनुसार, 2024-2025 के दौरान एक संगठित आपराधिक समूह ने स्थानीय प्रशासन द्वारा सेना की रक्षा जरूरतों के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया। इन लोगों ने सेना के लिए खरीदे गए ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरणों के अनुबंधों में जानबूझकर कीमतें बढ़ाकर करीब 30 प्रतिशत तक की रिश्वत ली। ब्यूरो ने बताया कि इस घोटाले के तहत किया गया ड्रोन अनुबंध 2.4 लाख डॉलर का था, जिसमें 80 हजार डॉलर की अनावश्यक कीमत जोड़ी गई थी। ये सभी उपकरण यूक्रेन में ही स्थानीय स्तर पर निर्मित किए गए थे।

मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें एक सांसद, एक बर्खास्त अधिकारी, एक क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख, एक सैन्य प्रशासन के प्रमुख, नेशनल गार्ड यूनिट के कमांडर, और एक ड्रोन निर्माता कंपनी के निदेशक व मालिक शामिल हैं। हालांकि, जांच के हित में अभी किसी आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। यूक्रेन की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने सांसद को दो महीने की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है, साथ ही लगभग 1,90,000 डॉलर की जमानत राशि भी तय की गई है।

दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, जापान ने कम टैरिफ के लिए अमेरिका से किए समझौते

एजेंसी
वाशिंगटन। अमेरिकी टैरिफ के सात अगस्त को प्रभावी होने से पहले दक्षिण कोरिया, यूरीपय संघ और जापान ने महत्वपूर्ण घोषणा कर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के कोपभाजन का शिकार बनने से बचने की कोशिश की है। दक्षिण कोरिया ने अपने समझौते में कम टैरिफ दर सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करने और 100 अरब डॉलर की तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने पर सहमति जताई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में यह जानकारी दी गई है। साथ ही यूरोपीय संघ ने संकेत दिया कि वह 750 अरब डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा खरीदेगा और उसकी कंपनियां कम से कम 600 अरब डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार हैं। जापान ने कहा कि वह अमेरिका में निवेश के लिए 550 अरब डॉलर

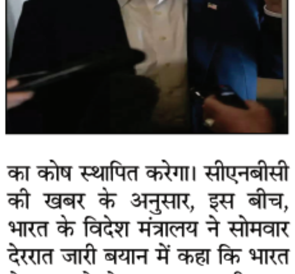

का कोष स्थापित करेगा। सीएनबीसी की खबर के अनुसार, इस बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार देररात जारी बयान में कहा कि भारत ने रूस से तेल आयात तभी शुरू किया जब 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई। मंत्रालय ने यूरोपीय संघ और अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा, यह उजागर हो रहा है कि भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं। भारत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रातों-रात सोशल मीडिया पर नई दिल्ली को और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल के आयात को लेकर उसे निशाना बना रहे हैंयूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, रूस के साथ यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 67.5 अरब यूरो (78.1 अरब डॉलर) था, जबकि 2023 में उसका सेवा व्यापार 17.2 अरब यूरो था। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत ने कहा कि इस समूह का व्यापार रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नई दिल्ली और मॉस्को के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी से पहले के 10.1 बिलियन डॉलर के व्यापार से लगभग 5.8 गुना अधिक है। भारत की यह प्रतिक्रिया ट्रंप के भारत पर शुल्क में काफी वृद्धि करने की धमकी के बाद आई है, हालाँकि उन्होंने उच्च शुल्क के स्तर को निर्दिष्ट नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह भारतीय निर्यात पर 25 फीसद शुल्क और एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की धमकी दी थी।

राजतंत्र समर्थित आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दुर्गा प्रसाई जेल से रिहा

एजेंसी
काठमांडू। राजतंत्र समर्थक और राजावादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दुर्गा प्रसाई को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के कुछ ही समय बाद प्रसाई ने सोशल मीडिया प्लेट फार्म फेसबुक पर देश और विदेश में नेपालियों को उनके समर्थन, सहायता और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया। जेल से रिहा होने के बाद पत्रकारों को संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए दुर्गा प्रसाई ने कहा कि जब जिला अदालत ने उन्हें कारावास का आदेश दिया, तब भी फैसले का सम्मान किया और स्वेच्छा से जेल चला गया तथा आज जब उच्च न्यायालय के आदेश से रिहा किया गया तो राष्ट्र निर्माण के लिए भविष्य की योजनाओं के साथ घर लौटा हूं। न्याय पालिका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रसाई ने कहा, मैं सभी सम्मानित न्यायाधीशों और पूरे अदालत परिवार को यह विश्वास दिलाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि देश में न्याय प्रणाली अभी मृत नहीं है। प्रसाई ने जेल प्रशासन, नेपाल पुलिस और साथी कैदियों के प्रति उनकी

कैद के दौरान सहयोग के लिए उनकी सराहना की। राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा, मैं देश के लिए था, हूं और हमेशा रहूंगा। सत्ता और शासन बदल सकती हैं, लेकिन मेरा चरित्र नहीं बदलेगा। काठमांडू जिला अदालत के आदेश के अनुसार प्रासाई को 13 जून को दिल्लीबाजार जेल भेजा गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आज कई लंबित मामलों में 28 लाख रुपये की जमानत के भुगतान पर उनकी रिहाई का आदेश दिया। अदालत के निर्देश के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

अमेरिकी टैरिफ पर छह महीने के लिए ईयू ने रोकी जवाबी कार्रवाई, ट्रंप से बनी अंतरिम सहमति

एजेंसी
ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में लागू की जाने वाली जवाबी कार्रवाई को छह महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाल ही में हुई एक अंतरिम समझ के बाद लिया गया है। ईयू आयोग के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।हालांकि यह समझौता एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। मसलन, शराब जैसे उत्पादों पर टैरिफ दरें तय नहीं हो पाई हैं। ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह जारी कार्यकारी आदेश के तहत अधिकांश ईयू उत्पादों पर 15 प्रतिशत शुल्क तय किया गया है, लेकिन कारों और कार-पुर्जों को कोई छूट नहीं मिली है। ईयू अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के और भी कार्यकारी आदेश जल्द सामने आ सकते हैं, जिससे स्थिति और स्पष्ट होगी। आयोग के प्रवक्ता ने कहा, 27 जुलाई को हुई सहमति के अनुरूप संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप देने के लिए ईयू अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 6 महीने के लिए अमेरिका के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई स्थगित करने की प्रक्रिया शुरू की है, जो 07 अगस्त से प्रभावी होने वाली थी।

सिविल सर्विस विधेयक में गड़बड़ी करने के लिए संसदीय समिति के अध्यक्ष और सचिव ही दोषी पाए गए

एजेंसी
काठमांडू। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश या इस्तीफे के दो साल तक किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्तियों में रोक लगाने संबंधी विधेयक में गड़बड़ी को लेकर गठित संसदीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संसदीय समिति के अध्यक्ष और सचिव को इसके लिए दोषी ठहराया गया है। इस जांच समिति के संयोजक जीवन परियार के अनुसार, रिपोर्ट में राज्य मामलों और सुशासन समिति के अध्यक्ष रामहरि खतिवडा और समिति के सचिव सूरज कुमार दुरा को कूलिंग पीरियड के प्रावधान को रद्द करने वाली भाषा डालने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दो दिन और दो रात की व्यापक चर्चाओं के बाद, समिति ने आम सहमति बनाते हुए मंगलवार सुबह स्पीकर देवराज घिमिरे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। परियार ने पुष्टि की कि रामहरि खतिवडा और सचिव दुरा की पहचान प्राथमिक जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में की गई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और विषयगत रूप से शामिल अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं। संसद में पंजीकृत संघीय सिविल सेवा विधेयक के मूल मसौदे में सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ पीरियड की

अनिवार्यता से बाहर रख दिए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, जबकि सत्ता साझेदार दलों ने यह सहमति की थी कि यह नियम सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। हालांकि, जब प्रतिनिधि सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, तो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देते हुए एक नया खंड - धारा 82 (4) डाला गया, जिसमें सेवानिवृत्त सचिवों और संयुक्त सचिव को छूट दिए जाने का प्रावधान रखा हुआ था। इसके अतिरिक्त, सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता वाले वाक्यांश को हटा दिया गया। संसद की राज्य व्यवस्था समिति में सहमति और पारित होने के बाद इसे हूबहू प्रतिनिधि सभा में पेश करना था। जब प्रतिनिधि सभा से यह बहुमत से पारित होकर राष्ट्रीय सभा में भेजा गया तब इसकी पोल खुली। राष्ट्रीय सभा में भेजे गए विधेयक में व्यापक फेरबदल किया जा चुका था। इस पर विवाद के कारण परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जांच करने के लिए संसदीय जांच समिति का गठन हुआ। रविवार की सुबह से सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक लगातार चर्चाओं के बावजूद, समिति शुरू में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रही। समिति को जांच के लिए 21 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 7 दिन का विस्तार किया गया था। मूल समय सीमा रविवार आधी रात को समाप्त हो गई, लेकिन विस्तारित विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने मंगलवार सुबह अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। समिति का समन्वय नेपाली कांग्रेस के सांसद और पार्टी के संयुक्त महासचिव जीवन परियार ने किया था। अन्य सदस्यों में नेपाली कांग्रेस की सुशीला थिंग, सीपीएन-यूएमएल की ईश्वोरी घर्ती और नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केंद्र से माधव सपकोटा, राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी से गणेश पराजुली और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के रोशन कार्की शामिल थे।

पांच वर्षों में 7.08 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी गई : पंकज चौधरी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों में लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, जिसमें लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की धोखाधड़ी भी शामिल है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पंकज चौधरी की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में सीजीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों ने 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी का पता लगाया है। वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी चोरी के 30,056 मामलों का पता चला। इनमें आधे से अधिक या 15,283 मामले आईटीसी धोखाधड़ी से संबंधित थे। इन मामलों में 58,772 करोड़ रुपये की कर चोरी की गई थी। उन?होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सीजीएसटी फील्ड अधिकारियों की ओर से 2.30 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया गया। इसमें 36,374 करोड़ रुपये की आईटीसी धोखाधड़ी शामिल थी। चौधरी ने सदन को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला, जिसमें 24,140 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी दावे शामिल थे।

भारत पर तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ के आरोप गलत - विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली । भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा रूस से तेल आयात को लेकर की जा रही आलोचना का कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत ने यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात शुरू किया, क्योंकि उस समय पारंपरिक तेल आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। जायसवाल ने बताया कि यह फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थितियों के कारण लिया गया ताकि भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्तियां यूरोप की ओर मोड़ दी गईं, जिससे भारत को रूस से आयात बढ़ाना पड़ा। यही नहीं, उस समय अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। बयान में कहा गया कि भारत के लिए यह कदम राष्ट्रीय जरूरत था, लेकिन जो देश आज भारत की आलोचना कर रहे हैं, वे स्वयं रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और वह भी बिना किसी मजबूरी के। विदेश मंत्रालय ने आंकड़े देते हुए बताया कि 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो था।

केंद्र ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के नकारात्मक प्रभाव की खबरों का किया खंडन

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है, जिनमें पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (ई20) के संभावित नकारात्मक प्रभाव, खासकर पुराने वाहनों और ग्राहक अनुभव के बारे में चिंता जताई गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हालांकि, ये चिंताएं काफी हद तक निराधार हैं और इसे लेकर वैज्ञानिक प्रमाण या विशेषज्ञ विश्लेषण का भी अभाव है। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से वाहनों को नुकसान पहुंचने या उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी होने की बात वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसमें तकनीकी आधार का भी अभाव है। कार्ब्युरेटेड और फ्यूल-इंजेक्टेड व्हीकल के पहले 1,00,000 किलोमीटर के दौरान हर 10,000 किलोमीटर पर टेस्टिंग के माध्यम से वाहनों के मैकेनिकल, एनर्जी और पर्यावरणीय प्रदर्शन पर इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण के उपयोग के प्रभाव पर इंटरनेशनल स्टडी से सांख्यिकीय रूप से पावर और टॉर्क जनरेटर तथा ईंधन की खपत में कोई अंतर नहीं दिखा।

इंडिगो ने लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए एसीएल एयरशॉप से किया करार

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने यूनिट लोड डिवाइस (यूएलडी) प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए अमेरिकी कंपनी एसीएल एयरशॉप के साथ करार किया है। एयरलाइंस ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह करार कार्गो और यात्री दोनों तरह के परिचालनों के लिए किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में एसीएल एयरशॉप का यह करार है। यूएलडी प्रबंधन में कार्गो और यात्रियों के बैगेज की हैंडलिंग शामिल है। इंडिगो के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (कार्गो) मार्क सच ने कहा कि यूएलडी की हमारी जरूरत बढ़ने के मद्देनजर एसीएल एयरशॉप के साथ साझेदारी कर हमें खुशी है। उन्होंने एयरलाइंस की जरूरत को ध्यान में रखते हुये सिर्फ दो महीने में पूरी तरह परिचालन शुरू कर दिया। एसीएल एयरशॉप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नहार्ड किंडलबैचर ने इंडिगो के साथ रणनीतिक साझेदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि यह वैश्विक यूएलडी प्रबंधन सेवा में अगुवा के रूप में कंपनी की स्थिति को और मजबूत करता है।

केंद्र ने बंगाल के विकास के लिए दिए 1.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा: शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास, गांव-गरीब और मजदूरों के कल्याण तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही पश्चिम बंगाल को 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के जरिए दी गई है।केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16,505 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 25,798 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और आरएसईटीआई के तहत 274 करोड़ रुपये, मनरेगा (2014-15 से 2022 तक) 54,465 करोड़

रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3,881 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 8,389 करोड़ रुपये सीधे पश्चिम बंगाल के गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के गांव, गरीब और मजदूरों के जीवन में परिवर्तन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वह पक्का घर हो, सड़क हो, आजीविका या रोज़गार हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में बुरी तरह विफल रही है। 2019 से 2022 के बीच केंद्र की टीमों ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच की, जिसमें मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। इनमें कार्यस्थल पर वास्तविक कार्य न होना, नियम विरुद्ध कामों को हिस्सों में तोड़ना, धन की हेराफेरी जैसी गंभीर बातें उजागर हुईं। इसी के चलते ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा अधिनियम की धारा 27 के तहत पश्चिम बंगाल का फंड रिलीज़ करना रोकना पड़ा है।

शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी शिकायतें मिलीं कि राज्य सरकार ने अपात्र परिवारों का चयन किया, पात्रों को हटाया और योजना का नाम बदलकर नियमों की अनदेखी की। ये सारी शिकायतें राष्ट्रीय और केंद्रीय मॉनिटरिंग टीमों द्वारा सही पाई गईं। केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सुधार या पारदर्शिता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दुर्भाग्यवश, पश्चिम बंगाल सरकार विश्वास, जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार बंगाल के लोगों के विकास, कल्याण और अधिकारों के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी रहेगी।

जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड का आईपीओ 7 अगस्त को खुलेगा, प्राइस बैंड 139-147 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

मुंबई/नई दिल्ली। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निवेशकों के लिए 7 अगस्त को खुलेगा। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 139-147 रुपये प्रति शेयर तय किया है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर 14 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हो सकते हैं। कंपनी ने जारी एक बयान में बताया कि ये आईपीओ गुरुवार, 7 अगस्त को खुलेगा, निवेशक इसमें निवेश करने के लिए 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 139-147 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड इस इश्यू से 3,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के 10 रुपये प्रति शेयर फेस वैल्यू वाले आईपीओ में निवेशक कम से कम 102 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके बाद 102 शेयर के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 1,600 करोड़ रुपये के नए शेयर किए जाएंगे। इसमें 2,000 रुपये करोड़ के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) भी शामिल है। कंपनी नए शेयरों से मिले पैसों में से 800 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल राजस्थान के नागौर में नई सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए करेगी। इसके अलावा 520 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल कंपनी के कुछ कर्ज चुकाने या कम करने के लिए होगा, जबकि बाकी शेष राशि जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड भारत की एक सीमेंट निर्माण करने वाली कंपनी है, जो हरित (ग्रीन) सीमेंट उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित है। ये कंपनी मिश्रित सीमेंट का उत्पादन करती है। भारत और विश्व की दूसरी सीमेंट कंपनियों की तुलना में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबसे कम है।

रेप्को बैंक ने अमित शाह को 22.90 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा

एजेंसी

नई दिल्ली। रेप्को बैंक ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 22.90 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा। इस अवसर पर शाह ने बैंक की सराहना करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस बैंक ने दक्षता, समर्पण और व्यावसायिकता का एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो सहकारी क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।रेप्को बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 140 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है और 30 प्रतिशत का लाभांश दिया, जो सहकारी समिति के इतिहास में सर्वाधिक है। गृह मंत्री ने बैंक की टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस मौके पर रेप्को बैंक के अध्यक्ष ई. संथानम, निदेशक एवं रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष सी. थंगराजू और प्रबंध थे।रेप्को बैंक, भारत सरकार का एक उद्यम है, जिसमें भारत सरकार की 50.08 प्रतिशत हिस्सेदारी है और

निदेशक ओ.एम. गोकुल ने केन्द्रीय मंत्री को लाभांश चेक सौंपा। कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सचिव, सीमा प्रबंधन डॉ. राजेंद्र कुमार भी उपस्थित यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह बैंक पिछले तीन दशकों से लगातार लाभ कमा रहा है और नियमित रूप से लाभांश घोषित करता आ रहा है।

कैट से जुड़े व्यापारियों ने किया संसद भवन का दौरा, ओम बिड़ला ने किया संबोधित

एजेंसी

नई दिल्ली। चांदनी चौक के सांसद एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन से जुड़े व्यापारियों को संसद भवन का दौरा किया। देशभर से आए करीब 150 प्रमुख व्यापारी नेताओं को नए और पुराने संसद भवन का भ्रमण कराया गया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस दौरे का मुख्य आकर्षण तब बना जब कैट व्यापारियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद परिसर स्थित अपने मीटिंग कक्ष में संबोधित किया। अपने संबोधन में बिड़ला ने कहा कि कैट व्यापारियों का देशव्यापी संगठन है, जो पूरे देश में व्यापारियों के लिए कार्य कर रहा है। व्यापारी और व्यापार देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी न केवल रोजगार सृजित करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने संबोधन में

कहा कि बदलते हुए आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को अपने स्तर को ऊंचा उठाना होगा। हम सभी को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा कि व्यापारियों को देश और अपने हित मे अब स्वदेशी समान बेचना और खरीदना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि व्यापार और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को उनके संज्ञान में लाया जाए, तो वे अधिक से अधिक व्यापार से जुड़े विषयों को संसद में चर्चा के लिए लाने का प्रयास करेंगे। सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि देश के व्यापारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारतीय सामान खरीदो और बेचो के आह्वान का पूर्ण समर्थन करते हैं। इसके लिए 10 अगस्त से पूरे देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान भारत के आर्थिक स्वाभिमान को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इलैक्ट्रिक कार निर्माण इकाई का किया उद्घाटन

एजेंसी

थूथुकुडी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने थूथुकुडी में स्थापित वियतनामी कंपनी विनफास्ट के एक इलेक्ट्रिक कार निर्माण इकाई का उद्घाटन किया और पहली कार की बिक्री की शुरूआत भी की। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन में भी भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में औद्योगिक निवेश से संबंधित 32,000 करोड़ रुपये के 41 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में भारत की राजधानी है। देश के कुल इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन का 40 प्रतिशत तमिलनाडु में उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि विरुधुनगर ज़िले में 1,052 एकड़ में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। हम अविकसित ज़िलों में बड़ी संख्या में

रोज़गार के अवसर पैदा करने वाले कारखाने स्थापित कर रहे हैं। राज्य में लगभग 32,554 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश से यहां के 50 हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा। द्रविड़ मॉडल सरकार ने तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देकर इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की है। हम लगातार निवेशक सम्मेलन और निवेशक बैठकें आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने चेन्नई, कोयंबटूर, जापान और स्पेन जैसी कई जगहों पर निवेशक सम्मेलन आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक कार निर्माण कंपनी विनफास्ट ने नींव रखने के 17 महीने के भीतर ही अपना उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं तमिलनाडु सरकार की ओर से कंपनी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री ने इससे पहले वियतनामी कंपनी विनफास्ट की ओर से थूथुकुडी में बनी इलेक्ट्रिक कार निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पहली कार की बिक्री शुरू की। उन्होंने संयंत्र में निर्मित पहली इलेक्ट्रिक कार पर हस्ताक्षर भी किए।

मजबूत ग्लोबल संकेतों की मदद से मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

एजेंसी

नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार की जा रही पूंजी की निकासी और अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितताओं का असर एक बार फिर भारतीय मुद्रा बाजार में साफ नजर आया। नकारात्मक माहौल और घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपया आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही डॉलर की तुलना में गिरावट का शिकार हो गया। आज डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा 11 पैसे फिसल कर 87.66 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा 87.55 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत जोरदार मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा रुपये ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 34 पैसे की तेजी के साथ 87.21 के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद भारत की मुद्रा और मजबूत होकर 87.19 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंची। इसके बाद विदेशी निवेशकों की स्टॉक मार्केट से अपनी पूंजी की निकासी शुरू करने से रुपया ऊपरी स्तर से 51 पैसे की गिरावट के साथ 87.70 के स्तर तक पहुंच गया। अंत में डॉलर की आवक में थोड़ी तेजी आई, जिसके कारण रुपये की स्थिति में थोड़ा सुधार भी हुआ। पूरे दिन के कारोबार के बाद डॉलर की तुलना में रुपये ने 11 पैसे की कमजोरी के साथ 87.66 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। फौरेक्स मार्केट के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत-अमेरिका के बीच होने वाले प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर बनी अनिश्चितता और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की पूंजी निकासी के कारण बाजार में लगातार नकारात्मक माहौल बना हुआ है।

सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोना आज 1,510 रुपये से 1,650 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा होकर एक बार फिर एक लाख रुपये के स्तर को पार कर गया है। हालांकि चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में उछाल के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,01,410 रुपये से लेकर 1,01,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 92,960 रुपये से लेकर 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 1,12,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट

सोना आज 1,01,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,01,410 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,01,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,010 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,01,410 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 92,960 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,01,410 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,01,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 93,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,01,560 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना महंगा हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 1,01,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 92,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जीएसटी अधिकारियों ने लोहा-इस्पात क्षेत्र में फर्जी आईटीसी गिरोह का भंडाफोड़ किया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय ने लोहा एवं इस्पात कारोबार में 47.12 करोड़ रुपये मूल्य के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की कथित धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि जीएसटी अधिकारियों ने लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में 47.12 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धोखाधड़ी से लाभ उठाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये मामला लगभग 261 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य के फर्जी चालानों के आधार पर कुल 47.12 करोड़ रुपये के आईटीसी का लाभ उठाने और उसे आगे बढ़ाने से जुड़ा है, जबकि

वास्तव में माल की आपूर्ति की ही नहीं गई। मंत्रालय ने बताया कि यह मामला सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयोग द्वारा किए गए व्यापक पहल का हिस्सा है, जो नकली आईटीसी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान को कम करने के लिए प्रेरित करता है। विभाग इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों को पहचानने और बाधित करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और सप्लाई चेन मैपिंग टूल का लाभ उठा रहा है। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।

सेल ने विशेष इस्पात आपूर्ति के साथ नौसेना के स्वदेशीकरण को मजबूत किया

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) जुलाई में भारतीय नौसेना के दो प्रमुख जहाजों आईएनएस 'अजय' और आईएनएस 'निस्तार' के लिए विशेष इस्पात की आपूर्ति करके भारत के रक्षा स्वदेशीकरण प्रयासों में अहम भूमिका निभा रही है।इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इन दोनों जहाजों में से आईएनएस 'अजय' को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) ने पिछले महीने जुलाई के दौरान लांच किया, जबकि आईएनएस निस्तार को पिछले महीने जुलाई के दौरान ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) द्वारा कमीशन किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस 'अजय' के लिए सेल ने जरूरत की पूरी डीएमआर ग्रेड स्टील प्लेट्स की आपूर्ति की है, जो इस उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात पोत की संरचनात्मक मजबूती और स्टील्थ क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आईएनएस 'अजय' गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) द्वारा निर्मित आठवां और अंतिम स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) है। इसी तरह से सेल ने हाल ही में कमीशन किए गए आईएनएस निस्तार के लिए विशेष ग्रेड प्लेट्स की जरूरत की पूरी मात्रा की सप्लाई की है।

मजबूत ग्लोबल संकेतों की मदद से मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

एजेंसी

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट के मजबूत संकेत, क्रूड ऑयल में आई कमजोरी और मेटल तथा ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में आई जोरदार तेजी ने आज घरेलू शेयर बाजार के कारोबार में भी तेजी ला दी। आज के कारोबार की शुरुआत भी मजबूती के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद पहले घंटे के कारोबार में लिवालों और बिकवालों की खींचतान के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में भी उतार-चढ़ाव होता रहा। हालांकि सुबह 11 बजे के थोड़ी देर पहले लिवालों ने अपना जोर बना दिया, जिसकी वजह से बाजार लगातार ऊपर चढ़ता चला गया। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.52 प्रतिशत और निफ्टी 0.64 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिनभर के कारोबार के दौरान रियल्टी, मेटल, डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह बैंकिंग, आईटी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में आज बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.76 प्रतिशत उछल कर आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 4 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 448.82 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 444.52 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 4.30 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,286 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,286 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,847 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 153 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,716 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,637 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,079 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 25 शेयर बढ़त के साथ और 5 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 43 शेयर हरे निशान में और 7 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 165.92 अंक की मजबूती के साथ 80,765.83 अंक के स्तर पर खुला। बाजार खुलने के आधा घंटा बाद बिकवाली के दबाव में ये सूचकांक 99.40 अंक की कमजोरी के साथ 80,500.51 अंक तक गिर गया। इसके बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बना कर सेंसेक्स को कुछ देर में ही हरे निशान में वापस पहुंचा दिया। दोपहर 11 बजे के बाद बाजार में चौतरफा खरीदारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से आज का कारोबार खत्म होने का थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 493.28 अंक उछल कर 81,093.19 अंक तक पहुंच गया। हालांकि आखिरी वक्त में हुई मुनाफा वसूली की वजह से ये सूचकांक ऊपरी स्तर से करीब 75 अंक फिसल कर 418.81 अंक की तेजी के साथ 81,018.72 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 30.70 अंक उछल कर 24,596.05 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के बाद पहले घंटे के कारोबार में उतार चढ़ाव होता रहा, जिसकी वजह से ये सूचकांक 11.35 अंक की कमजोरी के साथ 24,554 अंक तक गिर गया। इसके बाद बाजार में खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिसके कारण इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई।

आलिया
श्रद्धा कपूर
को सैयारा डायरेक्टर मोहित सूरी ने बताया बायस्ड, कहा कमर्शियल समझ रखती हैं एक्ट्रेस

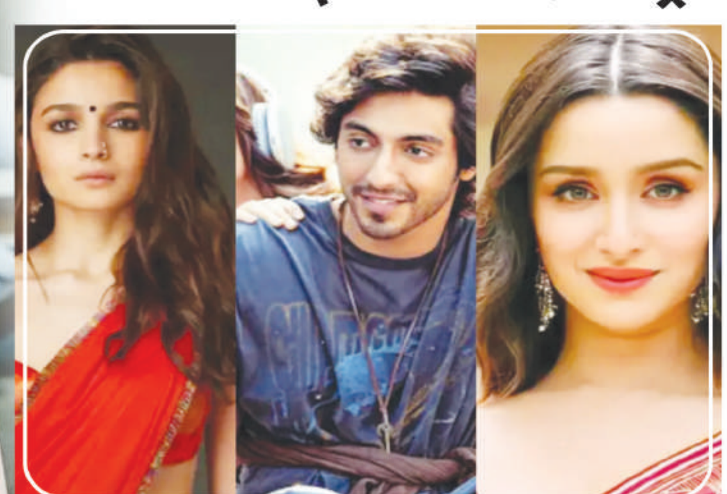

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। फैंस के अलावा क्रिटिक्स, स्टार्स ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की। आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर जैसी लीडिंग एक्ट्रेस ने सैयारा की तारीफ करते हुए इसे खास फिल्म बताया। लेकिन अब मोहित सूरी ने इन दोनों एक्ट्रेस की तारीफ को बायस्ड बता दिया। उन्होंने हाल में ऑडियंस और फिल्म सेलेब्रिटीज से फिल्म को मिल रहे प्यार पर बात की। मोहित ने आलिया और श्रद्धा को खुलकर बायस्ड बताया।

बायस्ड हैं श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट

हाल में आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर ने फिल्म सैयारा की तारीफ की थी। अब जूम को दिए एक इंटरव्यू में मोहित सूरी ने कहा, वो दोनों बायस्ड हैं। दोनों ने तो टीजर से ही फिल्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। वो मेरे प्रति बायस्ड हैं, लेकिन इस बात की ज्यादा अहमियत है कि बाकी दुनिया ने भी इस फिल्म को उतना ही प्यार दिया जितना उन्होंने।

आलिया का रिएक्शन आज भी है याद

बातचीत के दौरान मोहित ने बताया कि कैसे आलिया भट्ट ने उनके करियर की शुरुआती फिल्म वो लम्हे के गाने को लेकर पॉजिटिव रिएक्शन दिया था, जब वो बहुत छोटी थीं और इंडस्ट्री में नहीं आई थीं। मोहित बोले, मुझे याद है जब आलिया छोटी थी, तो मैं अपनी पहली फिल्म का वीडियो महेश भट्ट साहब को दिखाने गया था 'वो लम्हे वो बातें' का। भट्ट साहब को उतना समझ नहीं आया, लेकिन आलिया बोली 'पापा, ये बहुत कूल है, मैं बता रही हूं।' उस वक्त वो फिल्मों में थी भी नहीं, लेकिन उसमें वो समझ पहले से थी। वो हम सब से ज्यादा कमर्शियल सोच रखती है। मोहित ने बताया कि आलिया हमेशा से उनकी फिल्में 'मलंग', 'आशिकी 2' में उनके काम को देखती रही है, और मैंने भी उसका काम देखा है।

बबीता जी छोड़िए, 'तारक मेहता' की ये एक्ट्रेस सलमान खान के शो में लेगी एंट्री? पूरा सच पता लगा

एक बार फिर सलमान खान लौट रहे हैं. नए अंदाज में वो घरवालों की क्लास लगाते नजर आएंगे. 'बिग बॉस 19' की जल्द शुरुआत होने वाली है, जिसका एक प्रोमो भी सामने आ चुका है. जिसमें सलमान खान एकदम नेता वाले लुक में दिख रहे थे. क्योंकि इस बार का थीम ही राजनीति वाला है. खैर, 24 अगस्त को इस शो का प्रीमियर होगा. जिससे पहले कई एक्टर्स का नाम शो से जुड़ा. कुछ ने खुद क्लियर कर दिया है कि वो शो का हिस्सा नहीं होंगे. तो कुछ को शो का ऑफर मिला था, पर वो ठुकरा चुके हैं. इसी बीच 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की एक एक्ट्रेस की एंट्री की खबरें थीं, जो अब पूरा सच बता चुकी हैं.

यूं तो पहले कहा गया था कि बबीता जी भी इस सीजन में हो सकती हैं. जिन स्टार्स को अप्रोच किया गया है, उसमें उनका नाम भी है. वहीं बिग बॉस ताजा खबर पेज पर यह रिपोर्ट छपी कि, तारक मेहता के गुरुचरण सिंह को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है. साथ ही उनके साथ जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल भी शामिल होंगी. पर एक्ट्रेस ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

सलमान के शो में होगी ये एक्ट्रेस ?

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में एंट्री को लेकर जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने कहा कि वो शो का हिस्सा नहीं हैं. इन अफवाहों में भी कोई सच्चाई नहीं हैं. वो बताती हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है. दरअसल पिछले साल उन्हें सलमान खान के बिग बॉस के लिए ऑफर आया था. पर इस साल अप्रोच नहीं किया गया है. दरअसल एक्ट्रेस ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. जिसे लेकर शो भी छोड़ा था. हालांकि, अब नए इंटरव्यू में कई खुलासे किए और सबको हैरान कर दिया.

एक्ट्रेस ने बताया था कि प्रोड्यूसर उन्हें कहता था कि मन करता है तुम्हें किस कर लूं. हालांकि, यह बात वो बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता को बता चुकी थीं. जिसके बात असित मोदी को मुनमुन दत्ता ने डांट भी लगाई थी. हालांकि, शो के प्रोड्यूसर काफी विवादों में रहे हैं. अब चर्चा में आने के बाद अफवाहें उड़ी कि जेनिफर बिग बॉस में आएंगी. पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार अप्रोच ही नहीं किया गया है.

'मैं 6 महीने तक डिप्रेशन में थी...' इस पिक्चर के FLOP होने से टूट गई थीं करीना कपूर

बॉलीवुड सेलेब्स के साथ अक्सर ऐसा होता है जब उनकी कोई फिल्म नहीं चलती है तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है. स्टार्स को अपनी किसी न किसी फिल्म से बेहद लगाव रहता है और जब वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है तो उनका हाल काफी बुरा होता है. साल 1980 में अपनी फिल्म कर्ज के फ्लॉप होने के बाद ऋषि कपूर गहरे डिप्रेशन में चले गए थे. जबकि ऐसा ही हाल उनकी भतीजी और मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान का भी उनकी एक फ्लॉप फिल्म के बाद हो गया था.साल 2000 में अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म 'रिफ्यूजी' से डेब्यू करने वाली करीना कपूर खान ने अपने अब तक के 25 साल के करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया और कई बेहतरीन फिल्में दीं. उनकी कई फिल्में पिटी भी. उन्हीं में 'टशन' भी शामिल है. हालांकि ये पिक्चर एक्ट्रेस के दिल के काफी करीब रही है. इसके फ्लॉप होने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा था.

'टशन' क्यों है करीना के दिल के करीब ?

टशन साल 2008 में आई थी. इस पिक्चर में करीना ने सैफ अली खान और अक्षय कुमार के साथ काम किया था. बताया जाता है कि इस फिल्म के सेट पर ही सैफ और करीना की नजदीकियां बढ़ी थीं और इसी के सेट पर वो सैफ से मिली थीं. ऐसे में टशन के साथ करीना का खास नाता जुड़ गया था.

FLOP होने के बाद 6 महीने तक डिप्रेशन में रहीं

25 अप्रैल 2008 को रिलीज हुई टशन का डायरेक्शन विजय कृष्णा आचार्य ने किया था. अक्षय, सैफ और करीना की तिकड़ी से दर्शकों को काफी उम्मीद थी. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी. इसके फ्लॉप होने के बाद करीना 6 महीने तक डिप्रेशन में रहीं. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था,टशन के फ्लॉप होने के बाद मैं बुरी तरह टूट गई थीं. लगभग छह महीनों तक मैं डिप्रेशन में थी. मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया.

बजट भी नहीं निकाल पाई थी फिल्म

करीना कपूर की टशन का हाल इतना बुरा हुआ था कि ये अपना बजट भी नहीं वसूल पाई थी. मेकर्स ने इसे 31 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था. पिक्चर की भारतीय बॉस ऑफिस पर टोटल कमाई 29.44 करोड़ रुपये ही हो पाई थी.

इसलिए अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं सेलेब्स
तमन्ना भाटिया
ने बताया असली कारण

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को मिल्की ब्यूटी कहा जाता है। उनके चेहरे की रंगत पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। कुछ के मुताबिक एक्ट्रेस गोरा होने का ट्रीटमेंट लेती आई हैं। इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को लेकर कलाकारों को ट्रोल किया जाता है। ये मामला शेफाली जरीवाला की अचानक डेथ के बाद अधिक खबरों में बना रहा। अब तमन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों और ऐसे ब्यूटी ट्रीटमेंट का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी है। साथ ही बताया कि आज के समय में ये बहुत ही सामान्य बात है। आज की जनरेशन कॉस्मेटिक प्रोसीजर को लेकर सहज हैं और खुलकर बात करती हैं।

तमन्ना ने ब्यूटी ट्रीटमेंट पर रखी अपनी बात

लल्लनटॉप के साथ बातचीत में तमन्ना भाटिया ने कहा, लोगों को यह समझने की जरूरत है कि मीडिया की नजरों में रहने वाले लोगों के बारे में बात करना बहुत आसान है। क्योंकि आप उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, और आप कभी जान भी नहीं पाएंगे। इन बातों के बारे में हम बस चर्चा कर सकते हैं। इससे हम कहीं पहुंचते नहीं हैं।

इसलिए इस बारे में बात नहीं करते सेलेब्स

तमन्ना ने आगे कहा कि बोटोक्स जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अब टैबू नहीं हैं। लेकिन कोई नहीं चाहता उनपर सवाल उठें या उन्हें जज किया जाए। इसलिए अक्सर सेलेब्स अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट पर खुलकर बात नहीं करते। उन्होंने कहा, जेन-जी इसके बारे में खुले हुए हैं। जो भी ऐसा ट्रीटमेंट करवाते है वो उसपर खुलकर बात करते हैं। कोई भी जजमेंट से गुजरना नहीं चाहता। वो कुछ कहेंगे तो उनपर उंगलिया उठेंगी। फिल्मों में काम कर रहे लोगों को बहुत जज किया जाता है। वो शायद सहज नहीं हैं अपने लाइफ के बारे में शेयर करने को लेकर। बता दें, हाल में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की डेथ के बाद इंडस्ट्री में ब्यूटी ट्रीटमेंट पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में तमन्ना ने अपनी बात रखी है।

विधायक भवानी पठानियां की मुहिम लाने लगी रंग, कई दानी सज्जन आने लगे आगे

दिव्य दिल्ली : नूरपुर (विनय महाजन)

नूरपुर प्रदेश के विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा सिविल हॉस्पिटल फतेहपुर की रोगी कल्याण समिति के लिए चलाए गए मुहिम रंग लाने लग पड़ी है । क्षेत्र के दानी सज्जन खुल कर दान देने के लिए आगे आने लगे है ।डोनेशन अभियान के तहत फतेहपुर की जगनोली पंचायत के बलवीर ठाकुर ने 21000/- रुपए का चैक विधायक के माध्यम से अंशदान दिया।विधायक भवानी सिंह पठानिया ने दान के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि

सिविल हॉस्पिटल फतेहपुर में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए बहुत से सुधारों व अन्य संसधनो की जरूरत महसूस हो रही है। तत्काल राहत के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से ही सुधार संभव हैं। इसलिए यह डोनेशन अभियान चलाया गया है जिसमें लोग अपनी श्रद्धा से बढ़-चढ़कर दान दें रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया की अस्पताल के लिए प्रस्तावित अडिशनल नए भवन निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। अगले माह अस्पताले बनने बाले अडिशनल भवन की मुख्यमन्त्री सुख्विन्द्र सिंह शिलान्यास करेगें ।

जोन स्तरीय अंडर-14 से अंडर-19 खेल प्रतियोगिताओं की शुरूआत 18 अगस्त से

दिव्य दिल्ली : पठानकोट(करूनीत रंधावा)

पंजाब शिक्षा विभाग की ओर से स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार और जिला स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार की देखरेख में जोन स्तरीय अंडर-14 से अंडर-19 तक की खेल प्रतियोगिताओं की शुरूआत की जा रही है। जोन धार के 31 सरकारी स्कूलों की ये खेल प्रतियोगिताएं 18 अगस्त से 21 अगस्त तक थड़ा उपरला स्थित सीसे स्कूल में आयोजित होंगी। इसके लिए जोन इंचार्ज एवं सीसे स्कूल के प्रिंसिपल राजेश पठानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें धार जोन के कई स्कूलों के खेल सचिव शामिल हुए। जोन इंचार्ज प्रिंसिपल राजेश पठानिया ने बताया कि पंजाब शिक्षा विभाग के निदेर्शानुसार प्रतियोगिताओं में कबड्डी (लड़के व लड़कियां), खो-खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ झ लड़के व लड़कियां) और लड़कों की कुश्ती प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए खेल सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

पठानकोट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया

दिव्य दिल्ली : पठानकोट (करूनीत रंधावा)

पठानकोट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर श्री बालकृष्ण गोयल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त के निदेर्शानुसार विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम पठानकोट राकेश कुमार मीणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनजिंदर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

श्री गोयल ने सबसे पहले एक आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, इसके बाद सिविल अस्पताल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलिकपुर, उप-कारागार और महिला प्रकोष्ठ की जाँच की। उन्होंने बताया कि वे पंजाब के 6 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके तहत सरकारी योजनाओं की जीरो लेवल पर समीक्षा और संभावित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच की जा रही है। निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी और आवश्यकतानुसार पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चयनित स्थानों पर मानवाधिकार उल्लंघन की संभावना अधिक होती है, इसलिए विशेष रूप से इनकी जांच की जाती है, साथ ही संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से मानवाधिकारों का हनन न हो।

न्यूज फ्लैश

भारी बारिश से चंबा के भटियात में लैंडस्लाइड, दो घरों को भारी नुकसान

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

जिला चंबा के भटियात क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कल देर शाम घटासनी पंचायत के मामुल गांव में भूस्खलन हुआ, जिससे दो घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा। मलवे के साथ बड़े-बड़े पेड़ भी घरों में घुस गए। महिमा राणा पत्नी भूपेंद्र सिंह राणा के घर की दीवार और गेट टूट गए, जिससे मकान को खतरा पैदा हो गया। वहीं, संजना समयाल पत्नी स्व. सुशील समयाल के घर के आंगन में बड़ा पेड़ और पत्थर गिरने से भारी क्षति हुई। मलबे के कारण नीचे जाने वाले दोनों गांवों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सूचना मिलते ही बकलोह सोशल गोरखा वेलफेयर कमेटी के प्रधान कमल थापा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर रास्ता साफ किया। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को दो-दो तिरपाल और पांच-पांच हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की। नायब तहसीलदार सुशील धीमान ने आश्वासन दिया कि सरकार से हरसंभव सहायता दी जाएगी।

रजनी महाजन बनीं भाजपा संगठनात्मक जिला नूरपुर की सचिव, महिला वर्ग में उत्साह

दिव्या दिल्ली : नूरपुर (विनय महाजन)

भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिला नूरपुर की सचिव के रूप में रजनी महाजन की नियुक्ति पर महिला वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिला है। वर्तमान में नगर परिषद नूरपुर की उपाध्यक्ष रजनी महाजन ने इस अवसर पर पार्टी हाईकमान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, कांगड़ा-चंबा के सांसद राजीव भारद्वाज, नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का और जिला अध्यक्ष राजेश काका का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का सम्मान है। रजनी महाजन ने आश्वासन दिया कि वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस दायित्व को निभाते हुए संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगी। उनकी यह नई जिम्मेदारी पार्टी की गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस नियुक्ति पर भाजपा के प्रदेश और जिला नेतृत्व के साथ सभी कार्यकताओं ने हर्ष व्यक्त किया है।

गैलेक्सी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूरियां में भव्य मॉडल प्रदर्शनी, बच्चों की प्रतिभा ने बटोरी सराहना

दिव्या दिल्ली : नगरोटा

गैलेक्सी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूरियां में आज भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विषयों के विविध मॉडल प्रदर्शित किए गए। कई मॉडल वर्किंग थे, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। प्रदर्शनी का उद्घाटन स्कूल प्रबंधक निदेशक डॉ. गुलशन कुमार और निर्देशिका किरण लता वैद्य ने किया। इस दौरान बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे और उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की भरपूर प्रशंसा की। प्रदर्शनी में संस्कृत और हिंदी खंड में जगन्नाथ मंदिर, गोवर्धन पर्वत, ताजमहल, अयोध्या राम मंदिर जैसे आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए। कंप्यूटर में एआई स्मार्ट सिटी, विज्ञान में रॉकेट, इनवर्टर, ह्यूमन रेस्पिरेशन और वाटर प्यूरिफायर जैसे वर्किंग मॉडल थे। सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और आर्ट क्राफ्ट में भी बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य अनुराग शर्मा, उप प्रधानाचार्या श्वेता वैद्य और अन्य अध्यापक गण भी मौजूद रहे। समापन पर प्रबंधक निदेशक ने मॉडल प्रदर्शनी के शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को प्रोत्साहित किया।

सुनील शर्मा बने भाजपा जिला सिरमौर के उपाध्यक्ष, लंबे संगठनात्मक अनुभव का मिला सम्मान

दिव्य दिल्ली : सिरमौर

भाजपा जिला सिरमौर की नवनियुक्त कार्यसमिति में श्री रेणुका जी विधानसभा के दो बार मंडल महामंत्री रहे सुनील शर्मा को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनील शर्मा 2004 से संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़े समर्पित स्वयंसेवक हैं तथा अइश्ढ के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य भी रह चुके हैं। वे जम्मू-कश्मीर, रोहड़ू और शिमला ग्रामीण में संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और कई छात्र आंदोलनों व प्रदर्शनों का सफल नेतृत्व किया है। सोलन, शिमला और सुबाथू महाविद्यालयों में अइश्ढ की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में उनका अहम योगदान रहा।

सदर बाजार पंडित महासिंह कंपलेक्स की 198 दुकानों की सील हटी, मार्केट पूरी तरह खुली

दिव्य दिल्ली : सदर बाजार तेलीवाड़ा चौक पर पंडित महासिंह कंपलेक्स को मेट्रो द्वारा 198 में दुकानों को सील कर दिया गया था जिसको लेकर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के सदस्यों ने मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापारियों की समस्या को उनके समक्ष रख इसको देखते हुए मेट्रो ने बिल्डिंग का इंजीनियरों से सर्वे कराकर जांच कराई जिसके बाद शनिवार को दुकानों पर लगी हुई सील खोल दी गई और मार्केट पूरी तरह से खुल गई। इसी कड़ी में मानसिंह कंपलेक्स के व्यापारियों ने फेडरेशन के

सदस्यों का सम्मान समारोह रखा जिसमें फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव, महासचिव राजेंद्र शर्मा, कमल कुमार व कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल का स्वागत किया। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने कहा फेडरेशन का मकसद हमेशा व्यापारियों के हितों की आवाज उठाना और व्यापारियों की समस्या को हल करना होता है।जिसको लेकर वह समय-समय पर अधिकारियों व नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। इसको लेकर सभी व्यापारियों का सहयोग जरूरी है। पम्मा व राकेश यादव ने बताया अभी भी कुछ दुकान मेंन रोड की जो सील हुई पड़ी है उनको लेकर भी मेट्रो के अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा जारी है।

जिसे जो बिल्डिंग सही है उनकी दुकान जल्द से जल्द खुल सके। इस अवसर पर पंडित महासिंह कंपलेक्स के तरूण कौशिक, सौरभ गुप्ता, अमनदीप सिंह, इंदर सिंह नुरुल,धीरेंद्र कुमार, मेघा कौशिक, विनोद जैन, अक्षय सहित सैकड़ो व्यापारी उपस्थित थे।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया तो प्रदेश में अत्याधिक लोग बेघर व बेरोजगार

दिव्य दिल्ली : (नगरोटा सूरियां)

दी पौंग बांध विस्थापित व्यापार मंडल बस अड्डा नगरोटा सूरियां के प्रधान कृष्ण भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर, जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित न कर हटाने के निर्देश दिए गए हैं, विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर बड़ी संख्या में घर और दुकानें बन चुकी हैं। यदि इन्हें हटाया गया तो एक ओर जहां बड़ी संख्या में लोग बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे।

दिल्ली में 'बच्चन दि ग्रेट' ग्रुप के फैन्स ने मनाया अमिताभ बच्चन का 43वां रीबर्थ एनिवर्सरी

दिव्य दिल्ली : नई दिल्ली

बच्चन दि ग्रेट' ग्रुप के फैन्स ने मनाया बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का 43वां रीबर्थ एनिवर्सरी। कार्यक्रम का आयोजन मानसरोवर गार्डन के जागीर पैलेस होटल में किया गया। इस मौके पर पूरे देश से बच्चन के फैन्स पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चन साहब के पुनर्जन्म का केक काटकर हुआ। सेलिब्रेशन में फैन्स फिल्म डॉन की ड्रेस में पहुंचे और बच्चन के फिल्म के डायलॉग और गानों पर शानदार परफॉर्मेंस किए। बच्चन साहब की रीबर्थ एनिवर्सरी के आयोजक संजीव गुप्ता ने कहा,बच्चन जी की रीबर्थ एनिवर्सरी मना कर खुशी हो रही है। भारत सरकार द्वारा बच्चन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया

जाना चाहिए। करीब 2 महीने मुझे और मेरी पत्नी को कार्यक्रम की तैयारी करने में लगा और आज कार्यक्रम बेहद सफल रहा। मुख्य अतिथि निलेश बोड़ावाला ने कहा,आयोजक ने बहुत अच्छा अयोजन किया। ग्रुप के सदस्य समीर खत्री ने कहा,मेरी जिंदगी ही सिर्फ बच्चन है। 'बच्चन दि ग्रेट ग्रुप' के संस्थापक राजीव बेदी ने कहा,कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी और 2 अगस्त को उनको नई जिंदगी मिली थी। उन्होंने बताया बच्चन ने 18 टी-शर्ट ग्रुप के सदस्यों के लिए गिफ्ट में भेजे। बच्चन साहब ने हमारे ऑटोग्राफ और निमंत्रण पत्र को अपने ब्लॉक पर पोस्ट किया।इस सेलिब्रेशन में जुगल,गीता समीर खत्री,निलेश बोड़ावाला, राजीव मेहंदीरता, वाजिद, विक्रम, आदर्श, सुभाष,राजेश, दीपक, मनीष, शैलेश,मोहन, नीलेश पटेल, समीर वोहरा,आलोक श्रीवास्तव सहित कई अन्य फैन्स शामिल हुए। यह तीसरा साल था जब दिल्ली में फैन्स ने बच्चन साहब की रीबर्थ एनिवर्सरी धूमधाम से मनाया।

लाहौल-स्पीति में जनजातीय मेला 2025 के तहत भव्य वृक्षारोपण अभियान

दिव्य दिल्ली : केलांग

लाहौल-स्पीति जिला प्रशासन एवं वन विभाग के संयुक्त प्रयास से जनजातीय मेला 2025 को पर्यावरण अनुकूल और शून्य अपशिष्ट बनाने के उद्देश्य से केलांग के समीप बिलिंग गांव में एक भव्य वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त श्रीमती किरण भदाना, उप-मंडल अधिकारी आकांक्षा शर्मा, सहायक आयुक्त कल्याणी तिवाना, वन मंडल अधिकारी अनिकेत वानवे सहित सभी प्रशासनिक और सरकारी विभागों के प्रमुखों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि लाहौल-स्पीति जैसे संवेदनशील क्षेत्र में वृक्षारोपण पर्यावरण संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित विरासत सुनिश्चित करने का माध्यम है। वन मंडल अधिकारी ने बताया कि स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों का चयन कर क्षेत्र की जैव-विविधता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अभियान में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही और शून्य कचरा नीति को अपनाते हुए जैविक एवं पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का प्रयोग किया गया। वन विभाग ने इस पहल को हर वर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

हमीरपुर में चील बाहल से कोहली तक अक्टूबर तक तैयार होगी 17 किमी टू लेन सड़क

दिव्य दिल्ली : हमीरपुर

हमीरपुर जिला में लोगों को जल्द ही चील बाहल से कोहली तक टू लेन सड़क की सुविधा मिलने वाली है। नादौन उपमंडल के चील बाहल से हमीरपुर के कोहली तक 17 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण कार्य अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस सड़क में तीन बड़े पुलों का निर्माण भी शामिल है। इनमें से एक पुल कमलाह के पास पूरी तरह तैयार हो चुका है, जबकि बाकी दो पुलों पर स्लैब डालने का कार्य बारिश के कारण लंबित है। यह परियोजना मटौर से शिमला तक बन रहे फोर लेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे जे इन्फोटेक लिमिटेड द्वारा तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जहाँगीर हसन ने बताया कि बरसात के चलते थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन तय समय में काम पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी इस परियोजना पर खुशी जताई और कहा कि सड़क बनने से यात्रा समय बचेगा और आवागमन सुगम होगा।

भद्रोया में स्वामी जगत गिरी आश्रम को चक्की दरिया के कटान से खतरा

दिव्य दिल्ली : पठानकोट(करूनीत रंधावा)

भद्रोया स्थित डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम में चक्की दरिया के लगातार तेज बहाव और भारी बारिश के चलते आश्रम की भूमि का कटान गंभीर खतरे का रूप ले चुका है। वर्ष 2023 में आई भारी बाढ़ के दौरान आश्रम का मार्ग पानी के साथ बह गया था, जिसके बाद जगत गिरी आश्रम ट्रस्ट ने 15 लाख रुपये खर्च कर रास्ता दोबारा बनवाया। अगले ही वर्ष भारी बरसात से यह मार्ग फिर बह गया, जिसे श्रद्धालुओं ने 15-20 लाख रुपये की लागत से दोबारा बनाया। हिमाचल सरकार की ओर से लगाए गए मात्र 6 लाख रुपये के करेट भी इस बार तेज बहाव में बह गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय भी इस वर्ष फिर से नदी के तेज बहाव में बह गए हैं।

नूरपुर में 15-16 अगस्त को होगा राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव, तैयारियों की समीक्षा बैठक

लॉटरी तो राजीव बिंदल की निकली है क्योंकि भाजपा की आपसी तकरार के चलते राजीव बिंदल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला

दिव्य दिल्ली : नूरपुर (विनय महाजन)

नूरपुर में आगामी 15 और 16 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज एसडीएम अरुण शर्मा की अध्यक्षता में दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। एसडीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा और महोत्सव की भव्यता को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद को मेला स्थल पर मूवेबल टॉयलेट्स और सफाई की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और अस्थायी पानी के नल लगाने, जबकि बिजली बोर्ड को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को पहले ही कार्य आवंटित किए जा चुके हैं और तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। महोत्सव में श्रद्धालुओं के वाहनों की सुगम पार्किंग के लिए बचत भवन के पास विशेष पार्किंग स्थल की व्यवस्था होगी। 15 और 16 अगस्त की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों का चयन भी शीघ्र किया जाएगा। महोत्सव की निगरानी और समन्वय के लिए तहसीलदार राधिका सैनी को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसडीएम ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि जन्माष्टमी महोत्सव श्रद्धा, उत्साह और व्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। बैठक में उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रीतपाल सिंह, तहसीलदार राधिका सैनी, पीडब्ल्यूडी एसडीओ बलविंद्र सिंह, ईओ इंडस्ट्रीज अर्जुन वर्मा, खनन अधिकारी सुरेश कुमार, मंदिर कमेटी के प्रधान दविंदर शर्मा, सदस्य नरेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बघार मोड़ पर बजरी से भरा ट्रक पलटा, करीब 45 मिनट तक हाइवे पर लगा जाम

दिव्य दिल्ली :पठानकोट (करूनीत रंधावा)

पठानकोट-डलहौजी हाइवे पर बघार मोड़ स्थित जन्नत रेस्टोरेंट के सामने बीती रात बजरी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बुधवार सुबह ट्रक को दो क्रेनों की मदद से सीधा करने के दौरान करीब 45 मिनट तक दोनों ओर से यातायात पूरी तरह जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस सड़क सुरक्षा फोर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात बहाल करवाया। पुलिस कर्मी महेन्द्रजीत सिंह और बलजीत सिंह के अनुसार, ट्रक चालक सुभाष सिंह निवासी गांव दनेरा ने बताया कि वह हरियाल क्रेशर से बजरी भरकर चंबा की ओर जा रहा था।

ऊना को जोड़ने वाला रामपुर ब्रिज फिर आया सुर्खियों में, पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया चैनलाइजेशन कार्य

दिव्य दिल्ली : ऊना (ज्योति स्याल)

ऊना में पिछली बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ रामपुर ब्रिज एक बार फिर भारी बारिश के चलते सुर्खियों में है। हाल ही में हुई तेज बारिश से पुल के दोनों मुहाने सिल्ट, मलबा और रेत से भर गए, जिससे जलनिकासी में बाधा उत्पन्न हो गई। स्थिति को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने तत्काल

कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीनों की मदद से मुहानों की सफाई और ड्रेनेज लाइन बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ब्लॉक ऊना के एक्सईएन खुशविंदर सिंह ने बताया कि इस बार की बारिश से ऊना डिवीजन में लगभग 7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, विभाग ने सभी बंद रास्तों को खोल दिया है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। नदी-नालों की सफाई और सिल्ट हटाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397